सूर्योदय - 06:26
सूर्यास्त - 05 : 44

अधिकतम तापमान 32.0°
न्यूनतम तापमान 19.0°

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

ओपन सर्च

RNI No.DELHIN/2015/66886

खबरें और विज्ञापन के लिए सम्पर्क करें

Mob. : 9210092542
opensearchnews@gmail.com

E-mail | opensearchdelhi@gmail.com
Facebook | https://www.facebook.com/opensearch.co.in
Website | www.opensearch.co.in

वर्ष : 12 अंक : 344 नई दिल्ली, बुधवार 18 नवम्बर-2026
नई दिल्ली, हरियाणा, बिहार से प्रकाशित
` मूल्य : 02 रूपए | पृष्ठ : 08

'क्वाड' भारत के लिए भरोसेमंद और रचनात्मक साझेदारी : पीएम मोदी

इसी ऐतिहासिक शहर में एक बार फिर क्वाड बैठक होना एक महत्वपूर्ण पड़ाव है : पीएम मोदी

मनीला.एजेंसी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि 'क्वाड' भारत के लिए एक रचनात्मक और भरोसेमंद साझेदारी है। उन्होंने विश्वास जताया कि मनीला में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज, जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी बैठक क्वाड सहयोग के अगले चरण के लिए ठोस लक्ष्य तय करने में मदद करेगी।

बैठक के दौरान अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो, भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। फिलीपींस की राजधानी मनीला में आयोजित 'क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन' को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले साल जनवरी से अब तक क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की पांच बैठकें हो चुकी हैं।

यह चारों देशों की राजनीतिक इच्छाशक्ति और साझेदारी के प्रति उनकी मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मनीला और क्वाड का एक पुराना और खास रिश्ता रहा है। साल 2007 में चारों देशों के अधिकारी पहली बार यहीं मिले थे। इसके 10 साल बाद 2017 में भी इसी शहर में हमने फिर से अपना संवाद शुरू किया था।

आज इसी ऐतिहासिक शहर में एक बार फिर क्वाड बैठक होना एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। पिछले साल जनवरी से अब तक हमारे विदेश मंत्री पांच बार मिल चुके हैं। यह हमारी राजनीतिक इच्छाशक्ति और साझेदारी के प्रति साझा प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने आगे कहा, भारत के लिए क्वाड एक रचनात्मक और भरोसेमंद साझेदारी है। समुद्री सुरक्षा से लेकर विश्वसनीय सप्लाई चेन, नई तकनीकों से लेकर आपदा राहत तक, हमारा प्रयास रहा है कि क्वाड भरोसेमंद समाधान उपलब्ध कराए। मुझे पूरा विश्वास है कि आज की हमारी बैठक सहयोग के अगले चरण के लिए ठोस लक्ष्य तय करने में मदद करेगी।

'क्वाड' चार देशों भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका का एक समूह है। इसका उद्देश्य वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करना और एक खुले, स्वतंत्र, समावेशी, समृद्ध और मजबूत इंडो-पैसिफिक क्षेत्र को बढ़ावा देना है। 'क्वाड' की शुरुआत 2004 में हिंद महासागर क्षेत्र में आई सुनामी के बाद हुई थी।



मोदी और फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर की मनीला में मुलाकात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनीला में 23वें भारत-आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान फिलीपींस गणराज्य के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर. मार्कोस जूनियर से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने रणनीतिक साझेदारी के तहत रक्षा, सुरक्षा, अंतरिक्ष, रेलवे, फिनटेक और व्यापार-निवेश में बढ़ते सहयोग की सराहना की और क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों पर विचार साझा किए। विदेश मंत्रालय (एमईए) के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति फर्डिनेंड रोमुअलडेज मार्कोस जूनियर को 'आसियान' की अध्यक्षता सफलतापूर्वक निभाने के लिए बधाई दी। उन्होंने 2024 से 'आसियान' में भारत के लिए 'कंट्री कोऑर्डिनेटर' के रूप में फिलीपींस की भूमिका और आसियान-भारत संबंधों को मजबूत करने में उनके निरंतर सहयोग की सराहना की।

राष्ट्रपति ने मलेरिया अनुसंधान संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह का किया उद्घाटन

आईसीएमआर जैसे प्रमुख संस्थान विकसित भारत के स्वास्थ्य-संबंधी लक्ष्यों को अनुसंधान, सहयोग और नवाचार के माध्यम से प्राप्त करने में नेतृत्व कर सकते हैं : मुर्मु

नई दिल्ली.ओपन सर्च



राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने नई दिल्ली में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान के वर्ष भर चलने वाले स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि मलेरिया लंबे समय से भारत सहित दुनिया के कई देशों में एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती रहा है। स्वतंत्रता के समय, यह हमारे देश की सबसे गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक थी। यह संतोष की बात है कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में मलेरिया नियंत्रण में उल्लेखनीय प्रगति की है। बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, आधुनिक निदान तकनीकें, प्रभावी दवाइयां, मच्छर नियंत्रण अभियान और समुदाय की भागीदारी ने इस बीमारी के प्रसार को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मलेरिया उन्मूलन की दिशा में भारत की प्रगति को वैश्विक मान्यता मिली है।

मलेरिया लंबे समय से भारत सहित दुनिया के कई देशों में एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती रहा है। स्वतंत्रता के समय, यह हमारे देश की सबसे गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक थी : राष्ट्रपति

2024 में, भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन की 'हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट' श्रेणी से बाहर निकला। यह उपलब्धि हमारे सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों, वैज्ञानिकों, स्वास्थ्य कर्मियों और नागरिकों के सामूहिक प्रयासों से संभव हुई है। राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान ने मलेरिया के खिलाफ इस लंबी लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पिछले पांच दशकों में, इसने मलेरिया परजीवी, मच्छर, वेक्टर नियंत्रण, कीटनाशक प्रतिरोध, और समुदाय-आधारित निगरानी जैसे क्षेत्रों में अग्रणी अनुसंधान किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि जलवायु परिवर्तन, अनियोजित शहरीकरण, और मच्छरों की कीटनाशकों के प्रति बढ़ती प्रतिरोधकता जैसी नई चुनौतियां मलेरिया उन्मूलन में नई बाधाएं पैदा कर सकती हैं। ऐसे परिदृश्य में, केवल स्वास्थ्य कर्मियों के प्रयास मलेरिया के प्रसार को नहीं रोक सकते। जल जमाव को रोकने, मच्छर प्रजनन स्रोतों को समाप्त करने और पर्यावरण प्रबंधन पर भी ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नीति निर्माता और वैज्ञानिक समुदाय इस दिशा में संयुक्त प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि हाल के वर्षों में डेंगू भी देश में एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरा है। वैश्विक तापमान में वृद्धि और मानसून पैटर्न में बदलाव के कारण यह चुनौती और भी अधिक गंभीर हो सकती है।

लोक सभा अध्यक्ष ने बेंगलुरु में प्रथम राष्ट्रमंडल महिला सांसदों के भारत क्षेत्र सम्मेलन का किया उद्घाटन



बेंगलुरु.एजेंसी

लोक सभा अध्यक्ष, ओम बिरला ने आज सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं में महिलाओं के अधिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर बल दिया। बिरला ने कहा कि महिलाओं की केवल प्रभावी भागीदारी ही पर्याप्त नहीं, बल्कि नेतृत्व, नीति-निर्माण और कानून निर्माण में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। वर्ष 2023 में अधिनियमित 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' का उल्लेख करते हुए उन्होंने आशा व्यक्त की कि लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33% प्रतिनिधित्व का प्रावधान क्रियान्वयन की दिशा में आगे बढ़ेगा, जिससे महिलाओं का नेतृत्व पंचायतों से लेकर संसद तक बढ़ेगा। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि कई राज्यों ने पहले ही पंचायतों और नगरपालिकाओं में महिलाओं के 50% प्रतिनिधित्व का प्रावधान कर दिया है। विधायी संस्थाओं और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं की अधिक भागीदारी से सशक्त, अधिक संवेदनशील और जवाबदेह लोकतंत्र के निर्माण में मदद मिलेगी।

महिलाएं सार्वजनिक जीवन में संवेदनशीलता, प्रतिबद्धता और उत्तरदायित्व की भावना लाती हैं, जो समाज की आकांक्षाओं की पूर्ति करने और चुनौतियों का समाधान करने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए, बिरला ने उल्लेख किया कि नीति-निर्माण, कानून निर्माण और निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की अधिक भागीदारी लोकतंत्र को अधिक संवेदनशील, समावेशी और जवाबदेह बनाएगी।

उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में बस 300 फुट गहरी खाई में गिरी, 8 लोगों की मौत

टिहरी गढ़वाल.एजेंसी

उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में मंगलवार को ऋषिकेश से श्रीनगर जा रही एक बस पुल से लगभग 100 मीटर (करीब 328 फीट 1 इंच) नीचे खाई में गिर गई, जिससे 8 लोगों की मौत हो गई और 26 अन्य लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी सुबह करीब 5:30 बजे मिली। यह हादसा टिहरी जिले में ऋषिकेश-बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुलार इलाके के पास हुआ। हादसे की सूचना मिलते ही, ब्यासी और ढालवाला स्थित स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (एसडीआरएफ) की टीमें और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचीं और बचाव कार्य शुरू कर दिया। शुरुआती जानकारी के अनुसार, वाहन में लगभग 30-35 यात्री सवार थे। चार शव बरामद किए गए हैं और लगभग 20 लोगों को घायल अवस्था में बचा लिया गया है, जिन्हें एम्बुलेंस



के जरिए ऋषिकेश के अस्पताल ले जाया जा रहा है। घटना की गंभीरता को देखते हुए कमांडेंट अर्पण यदुवंशी के निर्देश पर एसडीआरएफ की अतिरिक्त टीमों को मौके पर भेजा गया है। पुलिस बल भी वहां मौजूद है और एसडीआरएफ और पुलिस मिलकर राहत एवं बचाव कार्य चला रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि बचाव कार्य जारी है और आगे की जानकारी का इंतजार है।

हादसे में मोहम्मद वहाब (झारखंड), राहुल कुमार (बिहार), अभिषेक (ऊधमसिंहनगर), प्रत्यूष पुत्र सुभाष (ऊधमसिंहनगर), अर्जुन सोरन (झारखंड), बुधन मुर्मू (झारखंड), 3 वर्षीय आयरा (असम), नूर जहां (असम), राजकुमार (झारखंड), जतिन (दिल्ली), पंकज नेगी (रुद्रप्रयाग), संतोष कुमार (बिहार),वीरेंद्र सिंह (चमोली), मुन्ना सिंह (झारखंड), सागर (उत्तर प्रदेश), खुशी भट्ट (पिथौरागढ़), परेश मराठी (झारखंड), आसापंथ (नैनीताल), पंकज कांडपाल (नैनीताल), अंजू (नैनीताल), आर्यन गुप्ता (मध्य प्रदेश), रमेश चंद (कोलकाता), दर्शन सिंह (नैनीताल), रामा प्रसाद घोष (कोलकाता), नवीन (नैनीताल) घायल हुए हैं। वहीं, एक व्यक्ति गंभीर अवस्था में है, जिसका नाम व पता अज्ञात है। इस बीच, एक अन्य दुखद घटना में, देर रात रुद्रप्रयाग में शादी समारोह से लौट रही एक एसयूवी लगभग 500 मीटर गहरी खाई में गिर गई, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई और छह अन्य घायल हो गए।

मोदी-धामी ने जताया दुख, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना



उत्तराखंड में ऋषिकेश-बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बस ऋषिकेश से श्रीनगर की ओर जा रही थी। हादसे में कई लोगों की मौत हो गई, जबकि बड़ी संख्या में यात्री घायल हो गए। हादसे की खबर पर प्रधानमंत्री मोदी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर किए गए पोस्ट में मोदी ने कहा, उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में हुई एक दुर्घटना में लोगों की जान जाने की खबर से बहुत दुख हुआ। दुख की इस घड़ी में, मैं पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं।

कार्यकर्ताओं के दम पर भाजपा 2027 में लगातार तीसरी बार हासिल करेगी ऐतिहासिक विजय : नितिन नवीन

मथुरा.एजेंसी

भारतीय जनता पार्टी की दो दिवसीय योजना बैठक मंगलवार को मथुरा के परखम स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय गो-विज्ञान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र में संपन्न हुई। बैठक के दूसरे दिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उपस्थित पदाधिकारियों और प्रतिनिधियों का मार्गदर्शन किया। इस दौरान आगामी तीन महीनों की कार्ययोजना, संगठनात्मक गतिविधियों, सहयोगी दलों के साथ समन्वय और वर्ष 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।

राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का उत्तर प्रदेश में यह पांचवां प्रवास है। इससे पहले वे पश्चिम, अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं। मथुरा पहुंचने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं मंत्री पंकज चौधरी तथा उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एवं बृजेश पाठक ने स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने परिसर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इसके पश्चात सभागार में विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय अशोक सिंघल की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया गया।



राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का यूपी में यह पांचवां प्रवास है। इससे पहले वे पश्चिम, अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 'गन्ना विकास रथ-2026' को दिखाई हरी झंडी

ओपन सर्च. संवाददाता

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित 'संवाद कक्ष' के सामने आयोजित कार्यक्रम में 'गन्ना विकास रथ-2026' अभियान की शुरुआत की। यह पहल बिहार सरकार के गन्ना उद्योग विभाग की ओर से आयोजित की गई है। मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी जिलों के लिए गन्ना विकास रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बिहार मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गन्ना किसानों की समृद्धि, गन्ना उत्पादन में वृद्धि और चीनी उद्योग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। वर्तमान में बिहार में 10 चीनी मिलें संचालित हैं, जबकि 5 और चीनी मिलें जल्द ही शुरू होने वाली हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 'समृद्ध



गन्ना किसानों की समृद्धि, गन्ना उत्पादन में वृद्धि और चीनी उद्योग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है : सीएम

उद्योग, सशक्त बिहार' की सोच के साथ शुरू किया गया यह अभियान आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक खेती और सरकारी योजनाओं की जानकारी सीधे किसानों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

नई चीनी मिलों की स्थापना और बंद पड़ी मिलों को फिर से चालू करके बिहार के चीनी उद्योग को मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि, गन्ने की खेती किसानों की आय बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इससे न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि, 'गन्ना विकास रथ-2026' किसानों को आधुनिक तकनीक और सरकारी योजनाओं से जोड़ेगा। साथ ही, बिहार में गन्ना उत्पादन और चीनी उद्योग के विकास को नई दिशा प्रदान करेगा। इस गन्ना विकास रथ के माध्यम से किसानों को गन्ने की उन्नत किस्मों, वैज्ञानिक खेती के तरीकों, जैविक खाद और आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा, 'गन्ना मशीनीकरण योजना' के तहत कृषि मशीनों की खरीद पर मिलने वाले अनुदान और 'मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम' के तहत प्रमाणित गन्ना बीजों पर उपलब्ध सब्सिडी के बारे में भी किसानों को जागरूक किया जाएगा।

सीएम ने स्वामित्व योजना से जुड़ी आपत्तियां दर्ज करवाने के लिए की स्वामित्व पोर्टल की लॉन्चिंग

कदम सिंह/ओपन सर्च ब्यूरो

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की लाल डोरा स्थित प्रोपर्टी के स्वामित्व से संबंधित शिकायतों व आपत्तियों के समाधान के लिए मंगलवार को एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में स्वामित्व पोर्टल की लॉन्चिंग की। इस दौरान हरियाणा के राजस्व मंत्री विपुल गोयल, राजस्व वित्तायुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा व मुख्यमंत्री के उप-प्रधान सचिव डॉ. यशपाल भी मौजूद थे।

सभी जिलों के उपायुक्तों सहित जिलों में नियुक्त राजस्व विभाग के उच्चाधिकारी भी ऑनलाइन माध्यम से बैठक से जुड़े। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसका घर और संपत्ति जीवनभर की मेहनत तथा परिवार की सबसे बड़ी पूंजी होती है। सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक नागरिक को

ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिक घर बैठे स्वामित्व पोर्टल पर दर्ज करवा सकेंगे संपत्ति संबंधी आपत्तियां एवं शिकायतें : मुख्यमंत्री नायब सैनी



प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसका घर और संपत्ति जीवनभर की मेहनत तथा परिवार की सबसे बड़ी पूंजी होती है, सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक नागरिक को उसकी संपत्ति का सही रिकॉर्ड मिले और उसके अधिकार सुरक्षित रहें : सैनी

उसकी संपत्ति का सही रिकॉर्ड मिले और उसके अधिकार सुरक्षित रहें। उन्होंने कहा कि हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र में 25 लाख प्रोपर्टी लाल डोरा में आती है जिसका स्वामित्व रिकॉर्ड पहले इनके मालिकों के पास नहीं था जिसके कारण इन्हें प्रोपर्टी की खरीद-बेच में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2018-19 में हरियाणा सरकार द्वारा स्वामित्व योजना शुरू की गई थी जिससे प्रभावित होकर केंद्र सरकार ने इसे पूरे देश में लागू किया। लाल डोरा स्थित प्रोपर्टी के असली मालिकों को उनका हक देने के लिए सरकार ने ड्रोन सर्वे करवाकर, टीमों को गांवों में भेजकर तथा आमजन की आपत्तियां लेकर प्रोपर्टी के मालिकाना हक को फाइनल किया तथा असली मालिक को हक देने के लिए नया कानून भी बनाया।

उन्होंने बताया कि आज प्रदेश में रेवेन्यू हरियाणा की वेबसाइट पर एक ही स्थान पर राजस्व संबंधी सभी सेवाएं आमजन के लिए उपलब्ध हैं। आज लॉन्च किए गए स्वामित्व पोर्टल के माध्यम से कोई भी व्यक्ति घर बैठे अपने जिला व गांव का नाम डालकर तथा अपने मोबाइल नंबर से लोगिन करके अपनी प्रोपर्टी का रिकॉर्ड देख सकता है।

सी.पी. राधाकृष्णन ने हरदीप सिंह पुरी को शपथ दिलाई



नई दिल्ली.ओपन सर्च

राज्यसभा के सभापति सी.पी. राधाकृष्णन ने संसद भवन में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले पुनर्निर्वाचित सदस्य हरदीप सिंह पुरी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। हरदीप सिंह पुरी ने अंग्रेजी में शपथ ली। इस अवसर पर लोकसभा सदस्य, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया; पंचायती राज मंत्री तथा मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह; और विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने की शहरी स्वामित्व योजना की समीक्षा

शहरी स्वामित्व योजना के तहत दुकानों के मालिकाना हक के लंबित मामलों का एक माह में निपटारा करने के दिए स्पष्ट निर्देश

ओपन सर्च ब्यूरो



चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शहरी स्वामित्व योजना 1.0 और शहरी स्वामित्व योजना 2.0 के तहत दुकानदारों को मालिकाना हक प्रदान करने से संबंधित सभी लंबित मामलों का एक माह के भीतर निपटारा सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि पात्र दुकानदारों को उनकी दुकानों का मालिकाना हक देने में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए संबंधित विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें और लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें।

मुख्यमंत्री मंगलवार को चंडीगढ़ में स्वामित्व योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में शहरी स्थानीय निकाय विभाग, राजस्व विभाग, विकास एवं पंचायत विभाग, लोक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग तथा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से संबंधित लंबित मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने जनहित में ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए 20 वर्ष से अधिक समय से किराये, लीज अथवा लाइसेंस फीस के आधार पर संचालित नगर निकायों की दुकानों का मालिकाना हक उनमें काबिज पात्र व्यक्तियों को देने का निर्णय लिया था। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना शुरू की गई थी, ताकि वर्षों से दुकानों का संचालन कर रहे लोगों को उनकी संपत्ति का कानूनी अधिकार मिल सके और वे सम्मान एवं आत्मविश्वास के साथ अपना कारोबार कर सकें।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता आम नागरिकों को उनकी संपत्ति का पूर्ण, वैध और निर्विवाद मालिकाना अधिकार दिलाना है। स्वामित्व का अधिकार मिलने से दुकानदारों को न केवल स्थायित्व मिलेगा, बल्कि वे अपनी संपत्ति का बेहतर उपयोग भी कर सकेंगे। सरकार की मंशा है कि पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से मिले और किसी भी व्यक्ति को विभागीय प्रक्रियाओं के कारण अनावश्यक परेशानी न उठानी पड़े।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन मामलों में विभिन्न विभागों की अनापत्ति, दस्तावेजों के सत्यापन अथवा अन्य औपचारिकताओं के कारण कार्य लंबित है, उनका आपसी तालमेल से शीघ्र समाधान किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित एक माह की समय-सीमा में लंबित मामलों का निपटारा सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी लेकर कार्य करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पारदर्शी, जवाबदेह और जनहितकारी प्रशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है। योजनाओं का वास्तविक लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना ही सरकार की कार्यशैली का मूल आधार है। बैठक में अधिकारियों ने अवगत कराया कि शहरी स्वामित्व योजना 1.0 के तहत अब तक कुल 13,601 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 7,224 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, जबकि 47 मामले लंबित हैं। इसी प्रकार, शहरी स्वामित्व योजना 2.0 के तहत कुल 1,781 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 311 मामलों में रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है।

बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त डॉ सुमिता मिश्रा, लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एके सिंह, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव विजय दहिया, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव अशोक कुमार मीणा, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव डॉ यश पाल, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव अजय कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

मधुमक्खी पालन प्रबंधन पर इंडो-इजराइल के तहत तीन दिवसीय प्रशिक्षण

ओपन सर्च ब्यूरो



करनाल। बागवानी विभाग हरियाणा द्वारा उद्यान प्रशिक्षण संस्थान उचानी में इंडो-इजराइल के तहत मधुमक्खी पालन प्रबंधन पर 19 नवम्बर तक तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एचएसएचडीए हरियाणा के मिशन निदेशक डॉ. मनोज कुमार ने भाग लिया। उन्होंने दीप प्रज्वलित करके प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उनके साथ डॉ. सत्येन्द्र यादव, प्रधानाचार्य भी मौजूद रहें। प्रशिक्षण के प्रथम दिन मधुमक्खी पालन प्रबंधन से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर तकनीकी सत्रों का आयोजन किया गया। जिसमें डॉ. सुमित सैनी, डॉ. गौरव सिंह व डॉ. मनदीप राठी ने विभिन्न विषयों पर प्रतिभागियों को जानकारी दी।

मधुमक्खियों के कॉलोनी संगठन, जीवन चक्र, परागण सहायता या पुष्प प्रबंधन मधुमक्खी कॉलोनी प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर तकनीकी ज्ञान से अवगत कराया गया। इसके अलावा प्रतिभागियों को मधुमक्खी पालन की आधुनिक तकनीकों, मौसमी प्रबंधन और वैज्ञानिक तरीकों से कॉलोनियों को मजबूत बनाने के बारे में भी विस्तार से बताया गया। इस प्रशिक्षण के दौरान विशेषज्ञों ने शहद उत्पादन, शहद के मूल्य संवर्धित उत्पादों तथा परागण प्रबंधन के महत्व पर भी प्रकाश डाला। प्रतिभागियों को मधुमक्खी पालन की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला, उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखने तथा बेहतर विपणन के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। इस प्रशिक्षण में भारत के विभिन्न राज्यों से 45 अधिकारियों द्वारा भाग लिया जा रहा है। इन्हें विशेषज्ञों द्वारा मधुमक्खी पालन प्रबंधन को लेकर विभिन्न जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त कर्नाटक से पहुंचे डॉ. सोमशेखर एस. हल्लोली, कार्यकारी निदेशक इस प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए।

महंगाई से जनता बेहाल, राहत के वादों के नाम पर धोखा कर रही सरकार : सैलजा

ओपन सर्च ब्यूरो



सिरसा। सिरसा की सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव कुमारी सैलजा ने बढ़ती महंगाई पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा सरकार के राहत के दावों और जनता के वास्तविक जीवन में बड़ा अंतर है। खाद्य पदार्थों से लेकर दैनिक जरूरत की वस्तुओं तक बढ़ती कीमतों ने गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों का बजट बिगाड़ दिया है। महंगाई कम करने के वादे करके सत्ता में आई सरकार जनता के साथ धोखा कर रही है।

कुमारी सैलजा ने प्रकाशित समाचार का हवाला देते हुए कहा कि अक्टूबर में थोक महंगाई दर 12.29 प्रतिशत तक पहुंचने और अरहर दाल के दाम में 26% बढ़ोतरी की खबर चिंताजनक है। कपड़ा, धातु, रसायन और बिजली उपकरणों की लागत बढ़ने का बोझ अंततः उपभोक्ताओं पर पड़ने की आशंका है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि आम आदमी को राहत कब मिलेगी।

सांसद ने कहा कि सीमित आमदनी वाले परिवार भोजन, बच्चों की पढ़ाई, इलाज और अन्य आवश्यक खर्चों के बीच संतुलन बनाने को मजबूर हैं। मजदूर, किसान, छोटे दुकानदार और पेंशन पर निर्भर बुजुर्ग लगातार दबाव झेल रहे हैं। जब कमाई के मुकाबले खर्च तेजी से बढ़ता है, तब विकास के सरकारी दावे लोगों को खोखले लगते हैं।

नाम बदलने से लाभ नहीं, अमृत सरोवर के खर्च की जांच हो : कुमारी सैलजा

कुमारी सैलजा ने अमृत सरोवर योजना पर प्रकाशित रिपोर्ट को लेकर कहा कि 223 करोड़ रुपये से अधिक खर्च के बावजूद गंदे, सूखे और अधूरे तालाब जवाबदेही मांगते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार घोटालों की सरकार बनती जा रही है। केवल योजनाओं के नाम बदलने और लोकार्पण से जनता को लाभ नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि एक के बाद एक योजनाओं में अनियमितताओं की खबरें गंभीर हैं। सरकार सरोवरों का स्वतंत्र भौतिक सत्यापन और खर्च का सामाजिक अंकेक्षण कराए। जहां गड़बड़ी मिले, वहां जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों पर कार्रवाई हो तथा सार्वजनिक धन की वसूली भी सुनिश्चित की जाए।

असम और हरियाणा के अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम करेंगे परस्पर सहयोग एवं समन्वय

- असम राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के प्रतिनिधिमंडल ने किया हरियाणा मुख्यालय का दौरा

ओपन सर्च ब्यूरो

चंडीगढ़। असम राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के उपाध्यक्ष सिमंता दास एवं निदेशक मंडल के सदस्यों ने हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के मुख्यालय का दौरा किया। इस अवसर पर हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष बलदेव सिंह ग्रोहा, प्रबंध निदेशक डॉ. वंदना दिसोदिया तथा निगम के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

इस दौरान दोनों निगमों के प्रतिनिधियों के बीच अनुसूचित जाति वर्ग के पात्र लाभार्थियों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के उद्देश्य से संचालित विभिन्न ऋण योजनाओं के संचालन और प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। बैठक में स्वरोजगार, उद्यमिता विकास तथा नए व्यवसाय स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के विभिन्न उपायों पर भी चर्चा हुई। इसके अतिरिक्त, ऋण वितरण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने, योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने तथा वितरित ऋणों की समयबद्ध एवं प्रभावी वसूली सुनिश्चित करने के लिए अपनाई जा सकने वाली रणनीतियों पर भी दोनों पक्षों ने अपने अनुभव साझा किए। दोनों निगमों के प्रतिनिधियों ने एक-दूसरे की योजनाओं, कार्यप्रणाली एवं सफल प्रयासों से सीख लेते हुए अनुसूचित जाति वर्ग के आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की दिशा में आपसी सहयोग एवं समन्वय बनाए रखने पर जोर दिया।

करनाल में धूल-वायु प्रदूषण पर लगेगी लगाम, 2 नई आधुनिक एंटी स्मॉग मशीनें सड़कों पर उतरी

जगमोहन आनंद, रेणु बाला गुप्ता और सलोनी शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

गीता देवी/ओपन सर्च ब्यूरो



करनाल। शहर में वायु प्रदूषण और धूल के कणों पर नियंत्रण पाने तथा नागरिकों को स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण उपलब्ध करवाने के लिए नगर निगम करनाल ने अपने प्रयासों को और तेज कर दिया है। इसी दिशा में नगर निगम द्वारा दो नई आधुनिक ट्रक माउंटेड एंटी स्मॉग गन वाटर स्प्रिंकलर मशीनें खरीदी गई हैं। मंगलवार को विधायक जगमोहन आनंद, महापौर रेणु बाला गुप्ता तथा नगर निगम आयुक्त सलोनी शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर इन मशीनों को शहर की सड़कों पर संचालन के लिए रवाना किया। दोनों छोटी आधुनिक मशीनों की कुल लागत 29 लाख 19 हजार रुपये है, जिसमें एक वर्ष का वार्षिक रख-रखाव भी शामिल है। इन मशीनों में 1,000 लीटर पानी की क्षमता वाले टैंक लगाए गए हैं। इनका मुख्य उद्देश्य शहर की आंतरिक सड़कों, भीड़भाड़ वाले बाजारों, व्यस्त मार्गों और धूल प्रभावित क्षेत्रों में पानी की महीन फुहारों के माध्यम से वातावरण में मौजूद धूल के कणों को नीचे बैठाना है। इससे सड़कों पर उड़ने वाली धूल में कमी आएगी और वायु गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

इस अवसर पर जगमोहन आनंद ने कहा कि करनाल शहर में वायु प्रदूषण एवं धूल के कणों को नियंत्रित करने के लिए नगर निगम द्वारा आधुनिक मशीनों की खरीद एक सराहनीय पहल है। वर्तमान समय में वायु गुणवत्ता को बेहतर बनाए रखना बेहद आवश्यक है। इन मशीनों के नियमित संचालन से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में उड़ने वाली धूल को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। विशेषकर व्यस्त बाजारों, आंतरिक सड़कों और अधिक आवाजाही वाले क्षेत्रों में इनका उपयोग नागरिकों को राहत प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि स्वच्छ वातावरण नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य से जुड़ा विषय है। वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव नवजात बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ता है। इसे कम करने के लिए नगर निगम प्रशासन और आमजन को मिलकर प्रयास करने होंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि इन आधुनिक मशीनों के प्रभावी संचालन से करनाल में वायु गुणवत्ता सुधारने और एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) को बेहतर बनाने के प्रयासों को मजबूती मिलेगी। महापौर रेणु बाला गुप्ता ने कहा कि शहर में वायु प्रदूषण और धूल नियंत्रण के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल समय की आवश्यकता है।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला : हरियाणा पवेलियन में विरासत और विकास का अद्भुत संगम : सांसद संजय भाटिया

ओपन सर्च ब्यूरो



चंडीगढ़। राज्यसभा सांसद संजय भाटिया और व्यापार मेला प्राधिकरण की मुख्य प्रशासक श्रीमती ए. मोना श्रीनिवास ने मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में बनाए गए हरियाणा पवेलियन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने पूरे पवेलियन का बारिकी से अवलोकन किया। इस अवसर पर संजय भाटिया ने कहा कि हरियाणा हर क्षेत्र में नंबर-1 है, इसकी झलक इस हरियाणा पवेलियन में भी देखने को मिल रही है। उन्होंने प्रदेशवासियों को अधिक से अधिक संख्या में इस मेले में पहुंचकर विरासत और विकास के इस अद्भुत संगम की झलकियां देखने का आह्वान किया। राज्यसभा सांसद संजय भाटिया ने कहा कि वे कई वर्षों बाद व्यापार मेले में आए हैं। इससे पहले वे स्कूल के समय बच्चों के साथ भ्रमण के दौरान यहां आए थे। आज हरियाणा पवेलियन में आकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा हर क्षेत्र में नंबर वन है। वर्ष 1966 में हरियाणा के गठन के बाद से लगातार लोगों का जीवन स्तर बदल रहा है और लोग खुशहाल हो रहे हैं। तकनीक के मामले में भी हरियाणा का कोई मुकाबला नहीं है।

पानीपत निर्यात के रूप में ही जाना जाता है

सांसद संजय भाटिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के दिशा निर्देश पर मेले में निर्यात कॉर्नर बनाया गया है। यह बेहद सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि उनका जन्मस्थान पानीपत है, जो विभिन्न उत्पादों के निर्यात के रूप में ही जाना जाता है। टेक्सटाइल निर्यात के मामले में पानीपत का भारत में अहम स्थान है। पवेलियन में उन्होंने फरीदाबाद और गुरुग्राम के अनेक उत्पाद भी देखे। उन्होंने करनाल लोकसभा क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व किया है। वहां का बासमती चावल, जिसकी खुशबू पूरी दुनिया में फैली हुई है, उसे भी उन्होंने आज पवेलियन में दिखाया गया है। हरियाणा पवेलियन में कृषि और निर्यात के संयोजन पर सांसद संजय भाटिया ने कहा कि इस बार यह बहुत सोच-समझकर तय किया गया बड़ा अच्छा संयोजन है। हरियाणा ने अपनी विरासत को भी संभालकर रखा है और आने वाली दुनिया के साथ भी कदम से कदम मिलाकर चल रहा है।

हरियाणा पवेलियन में प्रदेश के इतिहास से लेकर आज के विकास को दिखाया : ए.मोनाश्रीनिवास

हरियाणा व्यापार मेला प्राधिकरण की मुख्य प्रशासक श्रीमति ए. मोना श्रीनिवास ने कहा कि इस वर्ष के व्यापार मेले की थीम 'विकास और विरासत' है, जिसे हरियाणा पवेलियन में बेहद प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया गया है। हरियाणा की आध्यात्मिक और धार्मिक विरासत के साथ-साथ उसका इतिहास भी बहुत पुराना है।

डॉ. प्रियंका 'सौरभ' को 2.82 लाख के सम्मान, भिवानी गौरव पुरस्कार-2026 से अलंकृत

ओपन सर्च ब्यूरो



हिसार/भिवानी/सिवानी मंडी। साहित्य, पत्रकारिता एवं सामाजिक चिंतन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए हरियाणा की साहित्यकार एवं स्तंभकार डॉ. प्रियंका 'सौरभ' को भिवानी गौरव पुरस्कार-2026 से सम्मानित किया गया। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर-10 स्थित होटल क्राउन प्लाजा में आयोजित समारोह में उन्हें 2,51,000 की आजीवन गौरव सदस्यता तथा 31,000 का भिवानी गौरव साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया।

इस प्रकार उन्हें कुल 2,82,000 की सम्मान राशि से अलंकृत किया गया। इसके अतिरिक्त उन्हें प्रतिष्ठित नारायणी देवी भग्गनका ओजस्विनी सम्मान भी प्रदान किया गया। रविवार, 15 नवंबर 2026 को दिल्ली के क्राउन प्लाजा होटल, रोहिणी में आयोजित इस समारोह में परम संत हुजूर कंवर साहिब जी महाराज का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ।

उनके सानिध्य ने आयोजन को आध्यात्मिक गरिमा प्रदान की। समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए अन्य विभूतियों को भी सम्मानित किया गया। इनमें लोक प्रशासन एवं ग्राम विकास के लिए सांसद एन.डी. गुप्ता, शिक्षा के लिए डॉ. नरेश कौशिक, पत्रकारिता के लिए बलवान शर्मा, साहित्य के लिए डॉ. जोगेंद्र कुमार, खेल के लिए पूनम शर्मा, सेवा के लिए रामदेव तायल, कला एवं संगीत के लिए दिनेश रहन तथा राष्ट्रसेवा के लिए जीताराम गुप्ता (एडवोकेट) शामिल रहे।

इसके अतिरिक्त सेवामूर्ति सूरजमल कागड़िया, कुलदीप राज महाजन और जगन्नाथ सर्राफ के नाम से स्मृति सत्र भी आयोजित किए गए। राजनीति विज्ञान में पीएच.डी. डॉ. प्रियंका 'सौरभ' कवयित्री, साहित्यकार, स्वतंत्र पत्रकार, स्तंभकार एवं सामाजिक चिंतक हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में सक्रिय लेखन करते हुए उनके हजारों संपादकीय, लेख एवं विचार-आलेख प्रकाशित हो चुके हैं। उनके लेखन के प्रमुख विषय महिला सशक्तिकरण, स्त्री-अस्मिता, शिक्षा, ग्रामीण विकास, लोकतांत्रिक मूल्य और समसामयिक सामाजिक सरोकार हैं। डॉ. प्रियंका 'सौरभ' की 12 व्यक्तिगत तथा दो संपादित पुस्तकें प्रकाशित हैं।

उनकी प्रमुख कृतियों में 'दीमक लगे गुलाब', 'चूल्हे से चाँद तक', 'मौन की मुस्कान', 'खिड़की से झाँकती ज़िंदगी', 'परियों से संवाद', 'बच्चों की दुनिया', 'समय की रेत पर', 'निर्भयें', 'Fearless' और 'आँचल की चुप्पी' शामिल हैं। हरियाणवी भाषा एवं लोकसाहित्य के संरक्षण के लिए भी वे निरंतर सक्रिय हैं।

सुरजेवाला के बयान पर मंत्री अनिल विज का तंज, कहा 'चोरों को सारे नजर आते है चोर'

ओपन सर्च ब्यूरो

वोट चोर गद्दी छोड़ नारा इटली मेड, लोगों ने इस नारे को नकारा तो राहुल गांधी ने नारा चलाने के लिए इटली से एक्सपर्ट बुलाए : ऊर्जा मंत्री अनिल विज

चंडीगढ़। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस के नारे 'वोट चोर गद्दी छोड़' को इटली मेड बताते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। वहीं, सोनिया गांधी द्वारा लिखी किताब को लेकर 1984 के सिख दंगों और स्वर्ण मंदिर पर सेना की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने पंजाब में कानून व्यवस्था पर भी सरकार को घेरा।

इसके अलावा, गन्ने के दामों को लेकर सुरजेवाला के बयान पर पलटवार किया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस के नारे 'वोट चोर गद्दी छोड़' को विदेशी बताते हुए कहा कि इटली के राजनेता भारत में हुए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में वोट चोर गद्दी छोड़ नारा लगाते है और राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है वो ठहाके लगाकर हंसते है जोकि देशद्रोह है, उन्होंने कहा इससे ये साबित होता है ये नारा इटली मेड है। इटली में ये नारा बनाया गया है देश के विरुद्ध वातावरण बनाने के लिए और जब राहुल गांधी फेल हो गए, लोगों ने इस नारे को नकार दिया तो उन्होंने इटली से एक्सपर्ट बुलाए है इस नारे को आगे चलाने के लिए। सोनिया गांधी जी ने अपनी पुस्तक में बहुत कुछ लिखा है जिसमें कांग्रेस के कुकर्मों पर लीपापोती करने की कोशिश की गई है। 1984 में दिल्ली में सिख दंगों पर लीपापोती करने की कोशिश की है कि उन्होंने आंसू बहाये हैं। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने सवाल करते हुए कहा कि क्या सोनिया गांधी ने अपने पति को समझाया था बल्कि राजीव गांधी ने उन कत्लेआम को जस्टिफाई किया था और कहा था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है।

गोल्डन टेंपल पर सेना को जाना पड़ा, उसके ऊपर भी लीपापोती करती नजर आ रही है, लेकिन वे बताए कि ऐसे हालात क्यों पैदा हुए, किसने रोकने थे किसकी केंद्र में सरकार थी? आपकी सासू मां इंदिरा गांधी की सरकार थी, उन्हें बताना चाहिए क्यों ऐसे हालात पैदा हुए विज ने सोनिया गांधी को सलाह देते हुए कहा कि इन सवालों के जवाब देने के लिए सोनिया गांधी को एक और किताब लिखनी चाहिए।

शहीद स्मारक के समक्ष जल्द लगेगा एस्केलेटर, मंजूरी मिली, लोगों में आने में नहीं होगी दिक्कत : ऊर्जा मंत्री अनिल विज

ओपन सर्च ब्यूरो



चंडीगढ़। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज के प्रयासों से अब जल्द आजादी की पहली लड़ाई का शहीद स्मारक, अंबाला छावनी के समक्ष एस्केलेटर लगेगा। एस्केलेटर लगाने के लिए मंजूरी भी मिल गई है। इसके लगने से अब स्मारक में पैदल आने वाले लोगों को जीटी रोड क्रास करने में आसानी होगी। यह जानकारी ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने दी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि शहीद स्मारक के आगे नेशनल हाईवे (जीटी रोड) है।

सड़क पार करने में कोई दिक्कत न हो इसके लिए एस्केलेटर लगाने को मंजूरी मिल गई है और उसके आगे एस्केलेटर लगाया जाएगा। उन्होंने कहा जल्दी हम हरियाणा के सभी स्कूल व कालेज विद्यार्थियों को भी यह दिखाने की योजना बनाई जा रही है।

उन्होंने कहा कि शहीदी स्मारक आम जनता के लिए खोल दिया गया है, खोलने से पहले उन ज्ञात-अज्ञात क्रांतिकारियों को जिनको अंग्रेजों ने गोलियां मारी जिनको पेड़ों से टांग-टांग कर गोलियों से भूना गया, जिनको गोलिया मारी, जिनके गांव के गांव जला दिए उन आत्माओं की शांति के लिए हवन यज्ञ करके 15 नवंबर से शहीद स्मारक आम जनता के लिए खोल दिया गया है। उन्होंने कहा कि स्मारक में आने के लिए ऑनलाइन बुकिंग है और पहले महीने की सारी बुकिंग हो गई है। पहले ही दिन छत्तीसगढ़, पंजाब, जींद से भी लोग यह आए थे। ऐतिहासिक शहीद स्मारक का भव्य निर्माण कराने को लेकर अम्बाला प्रेस क्लब ने अनिल विज आभार व्यक्त किया है।

क्लब पदाधिकारियों ने कहा कि मंत्री अनिल विज ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर अंबाला प्रेस क्लब के सदस्यों ने मंत्री अनिल विज को फूलों का गुलदस्ता और दोशाला भेंट कर सम्मानित किया।

पत्रकारों ने शहीद-ए-आजम भगत सिंह की तस्वीर भेंट कर उनके प्रयासों की सराहना की। पत्रकारों ने कहा कि अंबाला की धरती का देश की आजादी के इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण स्थान रहा है।

ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने पत्रकारों का आभार व्यक्त किया

वहीं, पत्रकारों द्वारा सम्मानित किए जाने के बाद ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा की पत्रकारों से यह सम्मान पाकर वह गद गद महसूस कर रहे हैं हूँ। उन्होंने कहा कि यह जो राष्ट्रीय स्मारक अंबाला छावनी में बना है आजादी की पहली लड़ाई को समर्पित एक भी समारक सारे हिंदुस्तान में नहीं है। विज ने कहा अलग-अलग जगह पर अलग-अलग लोगों के समारक हो सकते हैं जैसे कहीं पर झांसी की रानी का हो सकता है, कहीं पर तात्या टोपे का हो सकता है तो कहीं पर मंगल पांडे का हो सकता है।

दिल्ली में महिला सुरक्षा पर अमित शाह के एक्शन प्लान का असर, ईआरएसएस का रिस्पॉन्स टाइम घटा, 6,000 से ज्यादा सीसीटीवी लगे

नई दिल्ली (एजेंसी)



सभी सार्वजनिक पार्कों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। अब तक 6,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। सभी पार्कों की फेंसिंग और बाउंड्री वॉल का काम 26 जनवरी 2027 तक पूर्ण करने के लिए कार्यवाही शुरू की गई है। 19,822 डार्क स्पॉट चिह्नित कर उन्हें सीसीटीवी कैमरों से कवर किया जा रहा है

दिल्ली में महिला सुरक्षा को लेकर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के निर्देश पर तैयार तीन महीने के एक्शन प्लान की प्रगति सामने आई है। 24 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस मुख्यालय में हुई बैठक में उन्होंने महिला सुरक्षा संबंधित तीन महीने का एक्शन प्लान बनाने के निर्देश दिए थे। अब नागरिक सुरक्षा, पीड़िता सहायता और प्रभावी अभियोजन के मोर्चे पर दिल्ली पुलिस ने कई अहम कदम उठाए हैं। सार्वजनिक पार्कों में सुरक्षा को लेकर बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। सभी सार्वजनिक पार्कों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं।

अब तक 6,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। सभी पार्कों की फेंसिंग और बाउंड्री वॉल का काम 26 जनवरी 2027 तक पूर्ण करने के लिए कार्यवाही शुरू की गई है। 19,822 डार्क स्पॉट चिह्नित कर उन्हें सीसीटीवी कैमरों से कवर किया जा रहा है। 1,635 सार्वजनिक पार्कों का सुरक्षा ऑडिट किया गया है। पार्कों की चारदीवारी, तारबंदी और प्रकाश व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। 503 बड़े पार्कों में गेट और नियमित गश्त 100 प्रतिशत में है। सार्वजनिक पार्कों के बाहर पीसीआर वाहनों की तैनाती सुनिश्चित की जा रही है। तकनीक को बढ़ावा देकर महिला सुरक्षा ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम 112 का रिस्पॉन्स टाइम 11:53 मिनट से घटकर 8:02 मिनट हो गया है। 178 पिंक स्कूटी प्रति स्कूटी औसतन 7.4 घंटे पेट्रोलिंग कर रही हैं। 35 ऑल-वुमेन पीसीआर वैन तैनात की गई हैं। दिल्ली पुलिस में महिला कर्मियों की हिस्सेदारी 17.3% है, जिसे 2030 तक 25% करने का लक्ष्य है। 125 पिंक बूथ पर रोज लगभग 308 वॉक-इन शिकायतकर्ता पहुंचते हैं। एयरपोर्ट, रेलवे और मेट्रो थानों में 24×7 महिला सहायता डेस्क हैं। हर जिले में मानव तस्करी रोधी इकाई है और संबंधित थानों, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और मेट्रो थानों में 24×7 महिला सहायता डेस्क संचालित हैं। शिष्टाचार अभियान के तहत 17,387 अभियान चले और 1,24,010 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई हुई। महिला पुलिस अधिकारियों द्वारा हॉस्टलों का दौरा और सुरक्षा ऑडिट भी किया जा रहा है।

सामुदायिक पहुंच के तहत कामकाजी महिलाओं के हॉस्टल, सह-शिक्षा स्कूल-कॉलेज और बालिका छात्रावासों में आउटरीच मजबूत की जा रही है। इसका मकसद जागरूकता बढ़ाना, भरोसा जीतना और सुरक्षा की भावना मजबूत करना है। आउटरीच कार्यक्रम के तहत 22,662 कार्यक्रमों से 15.9 लाख नागरिकों तक पहुंच बनी। सेल्फ-डिफेंस में 5.7 लाख और चाइल्ड सेफ्टी कार्यक्रमों में 3.4 लाख भागीदार जुड़े। लड़कियों के स्कूल, हॉस्टल, कॉलेज और कामकाजी महिलाओं के हॉस्टल में हर हफ्ते लगभग 3,514 विजिट हो रही हैं।

इनमें 1,869 विजिट बीट स्टाफ की और 882 एसएचओ की हैं। पुलिस की दृश्यता बढ़ाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की अगुवाई में पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और पीसीआर की संयुक्त गहन गश्त हो रही है। महिलाओं से संबंधित अपराधों में स्पीडी ट्रायल पर भी जोर दिया जा रहा है। 25 स्पेशल कोर्ट कार्यरत हैं और 37 अतिरिक्त कोर्ट स्थापित किए जा रहे हैं। 1 जनवरी 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक बलात्कार और पॉक्सो के 1,225 मामले दर्ज हुए। 81 प्रतिशत मामलों में चार्जशीट दाखिल हुई। दो माह की समय-सीमा में चार्जशीट का अनुपालन 94 प्रतिशत हुआ। 2025 में बलात्कार और पॉक्सो के मामलों में 99 प्रतिशत आरोप-पत्र दाखिल हुए। संवेदनशील मामलों में अनुभवी महिला अधिवक्ताओं सहित विशेष पब्लिक प्रॉसिक्यूटर नियुक्त किए जाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। अजनबी आरोपी वाले मामलों में एफआईआर से चार्जशीट तक औसत समय 59 दिन रहा। तेज जांच के उदाहरण के तौर पर नोएडा बस केस में 44 दिन और स्वरूप नगर ब्लाइंड मर्डर केस में 29 दिन में चार्जशीट दाखिल हुई।

आदतन अपराधियों की जमानत रद्द कराने और हाईकोर्ट में अपील में भी प्रगति हो रही है। आदतन यौन अपराधियों को जमानत न मिले, इसके लिए जमानत रद्दीकरण याचिकाएं दाखिल करने की पूरी प्रक्रिया का वैज्ञानिक खाका बनाकर एसओपी बनाई जा रही है।

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली

नई दिल्ली (एजेंसी)



नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। उनके वकील ने सर्वोच्च न्यायालय से सुनवाई टालने की मांग की थी। वकील ने कोर्ट को जानकारी दी थी कि आसाराम अब जेल मे सरेंडर कर चुके है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल आसाराम की याचिका पर ठंड की छुट्टियों के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।

बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट ने मई 2026 में निचली अदालत से मिली उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा था। 27 मई 2026 को राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच ने आसाराम को सामूहिक दुष्कर्म और आपराधिक साजिश के आरोपों से बरी कर दिया था। हालांकि, कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की अन्य गंभीर धाराओं के तहत उनकी दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा था। बीते महीने 27 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की मेडिकल पैरोल बढ़ाने की याचिका खारिज कर दी थी और मौजूदा अवधि समाप्त होने पर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था। आसाराम राजस्थान में 2013 के नाबालिग से दुष्कर्म मामले में जोधपुर की सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। जोधपुर की एक अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया था। राजस्थान उच्च न्यायालय ने उन्हें 6 अक्टूबर को 20 दिनों की पैरोल दी थी। उनके वकील ने मेडिकल आधार पर पैरोल बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आसाराम की चिकित्सीय पैरोल बढ़ाने की याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने आसाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था।

नई दिल्ली : जनता के लिए खोला जाएगा शीश महल, मंत्री प्रवेश वर्मा ने किया ऐलान

नई दिल्ली (एजेंसी)



दिल्ली सरकार ने मंगलवार को 'शीश महल' को लेकर बड़ा फैसला लिया है। शीश महल अब आम जनता के लिए खोला जाएगा। इसकी जानकारी खुद दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने दी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि 'शीशमहल' अगले सप्ताह से आम जनता के लिए खोला जाएगा। पहले इसे स्टेट गेस्ट हाउस बनाने का फैसला लिया गया था। इसके साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया कि कभी बंगला और गाड़ी नहीं लेने का दावा करने वाले व्यक्ति ने कई बंगलों को तुड़वाकर शीश महल बनवाया। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा, कई सालों से दिल्ली की जनता शीश महल को देखना चाहती थी। मैं दिल्लीवासियों को ये खुशखबरी देना चाहता हूं कि पिछली कैबिनेट की बैठक में यह तय हुआ था कि शीश महल को स्टेट गेस्ट हाउस बनाया जाएगा। मगर अब दिल्ली की जनता और मीडिया की मांग को देखते हुए ये तय किया गया है कि शीश महल को जनता के लिए खोला जाएगा। इसके लिए टिकट की बुकिंग कैसे करनी है, उसके बारे में बाकी जानकारी आपको आगे दी जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि सबसे पहला दौरा हम अपने मीडिया को करवाना चाहते हैं।

सबसे पहले देश की मीडिया को दिखाएंगे कि कैसे एक व्यक्ति जिसने कहा था कि मैं गाड़ी और बंगला नहीं लूंगा। पहले उसने कई बंगलों और सर्वेंट क्वार्टरों को तोड़ा, गैराज को तोड़ा, और फिर उसके बाद शीश महल बनवाया। शीश महल का केवल एक ही कमरा दिखाया जाता था, जहां पर बेमन से शहीद-ए-आजम भगत सिंह और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की फोटो लगी हुई थी। मंत्री प्रवेश वर्मा ने आरोप लगाया कि शीश महल के अंदर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं दी जाती थी। उसके अंदर करोड़ों रुपये के पर्दे लगे हुए हैं और वियतनाम का मार्बल लगाया गया है। इसको लेकर मैंने पहले भी यह जानकारी दी है। लेकिन अब जनता वहां का पूरा टूर कर पाएगी। अब जनता भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण खुद देख पाएगी। यमुना में सफेद झाग और आप नेता सौरभ भारद्वाज की कालिंदी कुंज से पानी पीने की चुनौती पर प्रवेश वर्मा ने कहा, 'दिल्ली में छठ महापर्व का आयोजन बड़े स्तर पर हुआ और करीब 2,500 घाटों पर पूजा कार्यक्रम हुआ। वहां लाखों लोगों ने इसमें हिस्सा लिया।

सोनिया गांधी किताब विमोचन पर राहुल ने अपनी गर्लफ्रेंड-कैंब्रिज के रेस्तरां का किया ज़िक्र : बोले- अगर प्यार में पड़ना है तो वर्सिटी रेस्तरां जाइए

नई दिल्ली (एजेंसी)



लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपनी मां और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की नई किताब 'बिलॉन्गिंगः अ जर्नी ऑफ़ लव' के विमोचन समारोह में एक बेहद हल्का-फुल्का और निजी अंदाज साझा किया। कार्यक्रम में राहुल गांधी ने न केवल अपने माता-पिता (राजीव गांधी और सोनिया गांधी) की पहली मुलाकात से जुड़ा किस्सा सुनाया, बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड का जिक्र कर सबको चौंका भी दिया।

कैंब्रिज के उस रेस्तरां में गर्लफ्रेंड संग गए थे राहुल, जहां मिले थे राजीव और सोनिया राजनीति से दूर रहकर सुनाई मां की कहानीः कार्यक्रम की शुरुआत में राहुल गांधी ने मुस्कुराते हुए कहा कि उन्हें मंच से राजनीति पर बात नहीं करने के सख्त निर्देश मिले हैं, लेकिन एक बेटे के तौर पर वह अपनी मां के बारे में कुछ खास बातें बताना चाहते हैं। उन्होंने सोनिया गांधी की कैंब्रिज के दिनों की एक पुरानी तस्वीर का जिक्र किया, जिसमें वे झूले से उलटी लटकी हुई थीं, और कहा कि उनकी मां का स्वभाव ऐसा ही बिंदास रहा है। 'वर्सिटी रेस्तरां' का दिलचस्प वाकयाः राहुल ने कैंब्रिज स्थित 'वर्सिटी रेस्तरां' का किस्सा सुनाते हुए बताया कि यही वह जगह है जहां उनके माता-पिता की मुलाकात हुई थी। राहुल ने कहा कि कई साल बाद जब वे कैंब्रिज गए, तो उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड से उस रेस्तरां में चलने को कहा, क्योंकि वे देखना चाहते थे कि उनके माता-पिता कहां मिले थे।

भविष्य के युद्ध की तैयारी में जुटीं तीनों सेनाएं, युद्ध पाठ्यक्रम की शुरुआत

नई दिल्ली (एजेंसी)



भविष्य के युद्ध में अब केवल मिसाइलें, लड़ाकू विमान और टैंक ही निर्णायक नहीं होंगे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर हमले, अंतरिक्ष आधारित अभियान, स्वायत्त हथियार प्रणालियां और सूचना युद्ध भी युद्ध का रुख बदल सकते हैं। इन नई चुनौतियों के बीच भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के अधिकारी अब भविष्य के युद्ध की रणनीतियों और तकनीकों को समझने के लिए एक साथ जुटे हैं। इसी उद्देश्य से 16 नवंबर को पांचवें त्रि-सेवा भविष्य युद्ध पाठ्यक्रम की शुरुआत हुई। इस युद्ध पाठ्यक्रम में तीनों सेनाओं के 40 सेवारत अधिकारियों के साथ रक्षा उद्योग से जुड़े प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। इस पाठ्यक्रम का उद्घाटन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने किया। उन्होंने बदलते युद्ध स्वरूप, उभरती तकनीकों और भविष्य के युद्धक्षेत्र में सामने आने वाली परिचालन चुनौतियों पर रणनीतिक चर्चा की शुरुआत की। इस पाठ्यक्रम में तीनों सेनाओं के अधिकारियों और रक्षा उद्योग के प्रतिनिधियों को एक साथ शामिल करने का उद्देश्य भविष्य के युद्ध को अलग-अलग दृष्टिकोण से समझना और संयुक्त सैन्य रणनीति विकसित करना है। दरअसल, दुनिया में युद्ध लड़ने के तरीके तेजी से बदल रहे हैं। अब किसी भी संघर्ष में केवल जमीन, समुद्र और आसमान में सैन्य ताकत का इस्तेमाल ही पर्याप्त नहीं है।

साइबर क्षेत्र में हमले, अंतरिक्ष में बढ़ती सैन्य गतिविधियां, एआई से संचालित प्रणालियां और विरोधी देश की सूचनाओं तथा सोच को प्रभावित करने की रणनीतियां भी महत्वपूर्ण होती जा रही हैं। ऐसे में सैन्य नेतृत्व के सामने चुनौती केवल नई तकनीकों को अपनाने की नहीं, बल्कि यह समझने की भी है कि इनका इस्तेमाल युद्ध के दौरान किस तरह किया जा सकता है। इस मौजूदा पाठ्यक्रम का चौथा संस्करण भी नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में आयोजित किया गया था। चार सप्ताह तक चले उस पाठ्यक्रम में थल सेना, नौसेना और वायुसेना के अधिकारियों के अलावा सरकारी संगठनों, शिक्षण संस्थानों, रक्षा उद्योग, वैज्ञानिक समुदाय और रणनीतिक विचार संस्थानों के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया था। इसमें भू-राजनीतिक बदलाव, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम तकनीक, साइबर युद्ध, संज्ञानात्मक युद्ध, सूचना युद्ध, स्वायत्त प्रणालियों और अंतरिक्ष आधारित सैन्य अभियानों जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई थी।

एनसीपी के दोनों गुटों के बीच विलय की बात कभी आगे नहीं बढ़ेगी : संजय राउत

नई दिल्ली (एजेंसी)

शिवसेना सांसद संजय राउत ने दावा किया है कि एनसीपी के दोनों गुटों के बीच विलय की बात कभी आगे नहीं बढ़ेगी। हाल के दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कुछ सप्ताह से एनसीपी के दोनों गुटों के संभावित विलय को लेकर अटकलों का बाजार गर्म था। नई दिल्ली में शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि मैं बार-बार कह रहा हूं कि विलय की बात कभी आगे नहीं बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि विलय क्यों होगा, किसलिए होगा, विलय का कारण क्या है? अजित पवार की अपनी पार्टी के अंदर ही इतनी गुटबाजी चल रही है।

आप देखेंगे कि हालात इतने बिगड़ जाएंगे कि हाथापाई तक की नौबत आ जाएगी। उस पार्टी में ऐसे ही हालात हैं। अब, वहां जाकर कौन लड़ाई-झगड़े में पड़ेगा। राउत ने अमित शाह की ओर से पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार की प्रतिमा का अनावरण करने पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने कार्यक्रम में अजित पवार को अपना घनिष्ठ मित्र बताया लेकिन सच्चाई यह है कि केंद्र सरकार ने अजित पवार को काफी परेशान किया। उन्होंने कहा कि अमित शाह के हाथों प्रतिमा का अनावरण होना अजित पवार के जीवनयात्रा की विडंबना है। पहले तो बदनाम किया, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। इतना परेशान कर दिया गया कि उन्होंने शरद पवार की पार्टी छोड़ दी। अब उनके दुनिया से जाने के बाद दोस्ती के कसीदे पढ़ रहे हैं। मैं फिर कहता हूं कि उनके हाथों प्रतिमा का अनावरण होना, उनके पूरे जीवन यात्रा की विडंबना है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था, इसलिए मैं यहां आया हूं। सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखूंगा। मैंने एक हलफनामा भी जमा किया है और मीडिया के सामने अपनी बात भी रखी है। मुझे जो समन भेजा गया है, वह मीडिया में दिए गए मेरे इसी बयान पर आधारित है कि आपने मीडिया में ऐसी-ऐसी बातें कही हैं।

फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामला : सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को मिली राहत बरकरार रखी

नई दिल्ली (एजेंसी)



सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान की दोषसिद्धि और सात साल की सजा पर रोक लगा दी गई थी।

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच ने खान की पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को भी इस मामले में उनकी दोषसिद्धि (कनविक्शन) पर रोक लगाकर राहत दी है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में दायर तीन अलग-अलग याचिकाओं से जुड़ा है। इनमें से एक याचिका उत्तर प्रदेश सरकार की है, जिसमें आजम खान को मिली राहत को चुनौती दी गई है। बाकी दो याचिकाएं अब्दुल्ला आजम खान और तजीन फातिमा की हैं, जिन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार करने के फैसले को चुनौती दी है। मई 2024 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में आजम खान की दोषसिद्धि और सात साल की सजा पर रोक लगा दी थी। हालांकि, हाई कोर्ट ने उनकी पत्नी और बेटे को ऐसी कोई राहत देने से मना कर दिया था, जबकि इन तीनों को ही जमानत मिल चुकी थी। हाई कोर्ट के इस फैसले से असंतुष्ट होकर उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची और मांग की कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता को दी गई इस राहत को रद्द किया जाए। इस बीच, अब्दुल्ला आजम खान और तजीन फातिमा ने अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने से हाई कोर्ट के इनकार को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने उन्हें भी इसी मामले में सात साल की कैद की सजा सुनाई है।

यह मामला 3 जनवरी 2019 का है, जब रामपुर से भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि आजम खान और उनकी पत्नी ने अपने बेटे के लिए दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाए थे। अभियोजन पक्ष के अनुसार, रामपुर नगर पालिका द्वारा जारी एक जन्म प्रमाण पत्र में अब्दुल्ला आजम की जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 बताई गई थी, जबकि दूसरे प्रमाण पत्र में उनकी जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 (लखनऊ में) दर्ज थी। 18 अक्टूबर 2023 को एक सत्र न्यायालय ने तीनों को दोषी ठहराया और कथित जालसाजी के इस मामले में उन्हें सात साल की कैद की सजा सुनाई। इन तीनों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया था, जिनमें धारा 420 (धोखाधड़ी), 467 (मूल्यवान दस्तावेज की जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), 471 (जालसाजी वाले दस्तावेज को असली बताकर इस्तेमाल करना) और 120-बी (आपराधिक साजिश) शामिल हैं।

इटली के नेता के बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल, तेलंगाना सरकार से माफी की मांग

नई दिल्ली (एजेंसी)

हैदराबाद में कांग्रेस की ओर से आयोजित भारत समिट-2026 में विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधि के भारतीय राजनीति में कथित हस्तक्षेप को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। जाहिद अली की ओर से अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की गई है। याचिका में इटली के नेता और यूरोपियन सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव जियाकोमो फिलिबेक के बयानों और 'वोट चोर, गद्दी छोड़' नारे पर सवाल उठाए गए हैं। इसके साथ याचिका में केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, तेलंगाना सरकार और भारत समिट के आयोजक समेत कुल 9 पक्षकार बनाए गए हैं। याचिका में विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधियों के भारत की घरेलू राजनीति में भाग लेने पर रोक लगाने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई है। इसके साथ ही तेलंगाना सरकार से सार्वजनिक माफी मांगने और भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए हलफनामा देने की मांग की गई है।

जाहिद अली ने याचिका में भारत समिट के आयोजन, विदेशी प्रतिनिधियों को दी गई अनुमति और वीजा शर्तों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी गठित करने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से संबंधित वीडियो हटाने और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की भी मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से इस याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की है। दरअसल, 14 नवंबर को हैदराबाद में आयोजित 'भारत समिट 2026' में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ जियाकोमो फिलिबेक ने मंच साझा किया था। अपने संबोधन के दौरान, फिलिबेक ने दावा किया कि भारतीय लोकतंत्र 'हमले की चपेट में' है और उसे 'हाईजैक' किया जा रहा है।

दिल्ली-एनसीआर में मौसम ने ली करवट, पारा गिरने से बढ़ेगी ठंड, वायु गुणवत्ता में सुधार

नई दिल्ली (एजेंसी)



दिल्ली समेत पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिल रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के ताजा पूर्वानुमानों के अनुसार, आने वाले दिनों में तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक, अब न केवल न्यूनतम तापमान बल्कि अधिकतम तापमान (दिन का पारा) में भी गिरावट आएगी। इसका सीधा असर यह होगा कि अब लोगों को सुबह और शाम के साथ-साथ दिन में भी हल्की ठंड का एहसास होने लगेगा। मौसम विभाग से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 17 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक के लिए 'मॉडरेट फॉग' (मध्यम कोहरा) का अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि, फिलहाल किसी भी प्रकार की चेतावनी नहीं दी गई है, लेकिन कोहरे के कारण दृश्यता प्रभावित हो सकती है। 17 नवंबरः अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहने की संभावना है। 18 नवंबरः तापमान में मामूली गिरावट दर्ज होगी।

अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम 13 डिग्री तक पहुंच जाएगा। 19 नवंबरः मौसम शुष्क रहेगा और तापमान 26 डिग्री (अधिकतम) और 13 डिग्री (न्यूनतम) के आसपास स्थिर रहेगा। 20 नवंबरः ठंड का असर बढ़ना शुरू होगा। अधिकतम तापमान गिरकर 25 डिग्री और न्यूनतम 13 डिग्री हो जाएगा। 21 और 22 नवंबरः महीने के तीसरे सप्ताह के अंत तक ठंड अपना रंग दिखाने लगेगी। दोनों ही दिनों में अधिकतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। मौसम में इस बदलाव के साथ एक राहत की खबर भी सामने आई है। फिलहाल तेज हवा के असर के चलते वायु गुणवत्ता सूचकांक में बदलाव देखा गया है। एनसीआर की हवा अब 'येलो' और 'ऑरेंज' जोन में पहुंच गई है, जिससे लोगों को सांस लेने में कुछ राहत मिली है। प्रदूषण के स्तर में यह गिरावट हवा की गति बढ़ने के कारण हुई है, जिससे प्रदूषक तत्व बिखर गए हैं। हालांकि, मौसम विज्ञानियों ने एक चेतावनी भी दी है।

भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन 18 नवंबर को पंजाब दौरे पर, 'समरसता संकल्प यात्रा' को दिखाएंगे हरी झंडी

नई दिल्ली (एजेंसी)



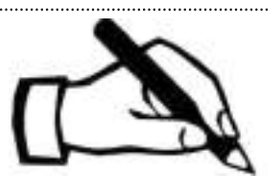
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बुधवार को पंजाब के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह वेडेरा सचखंड बल्लां में पूजा-अर्चना करेंगे। साथ ही, पार्टी की 16 दिवसीय 'समरसता संकल्प यात्रा' को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस अवसर पर नितिन नवीन जनसभा को संबोधित करेंगे और संत समाज के साथ संवाद भी करेंगे।

जालंधर आगमन के बाद नितिन नवीन बुधार दोपहर 1:10 बजे जालंधर स्थित डेरा सचखंड बल्लां के संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज मंदिर जाएंगे और पूजा-अर्चना एवं दर्शन करेंगे। दोपहर 1:35 बजे भाजपा अध्यक्ष जालंधर-पठानकोट जीटी रोड पर डेरा सचखंड बल्लां के समीप स्थित ग्राम रायपुर में 'समरसता संकल्प यात्रा' को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करेंगे और इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। बुधवार दोपहर 2:55 बजे नितिन नवीन रायपुर गांव में ही संत समाज के साथ सहभोज और संवाद कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती को वर्षभर चलने वाले राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मना रही है।

इस महाअभियान का शुभारंभ 29 जुलाई 2026 को गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर काशी से हुआ था। इस अभियान के तहत अब तक लगभग 29,000 'कलश वंदना यात्राएं' निकाली जा चुकी हैं, 30,000 से अधिक संतों से संपर्क किया गया है और सामाजिक समरसता का संदेश जन-जन तक पहुंचाने के लिए लगभग 51,000 स्थानों पर 'समरस दीप महोत्सव' आयोजित किए गए हैं। इसी राष्ट्रव्यापी अभियान को आगे बढ़ाते हुए 18 नवंबर से 3 दिसंबर 2026 तक 16 दिवसीय 'समरसता संकल्प यात्रा' का आयोजन किया जा रहा है। भाजपा अध्यक्ष द्वारा जालंधर से हरी झंडी दिखाए जाने के बाद यह यात्रा 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों- पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरेगी और कुल 2,402 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 3 दिसंबर को काशी में संपन्न होगी।

इस यात्रा के दौरान 100 से अधिक छोटी जनसभाएं और 17 बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें केंद्रीय मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी भाग लेकर संत रविदास के 'बेगमपुरा' (दुख-रहित समाज) और सामाजिक समानता के संदेश को जन-जन तक पहुंचाएंगे।

सम्पादकीय



कृषि विकास का नया आयाम है बागवानी

भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां खेती न केवल करोड़ों लोगों की आजीविका का आधार है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बदलते समय के साथ कृषि क्षेत्र में विविधता और नवाचार की आवश्यकता बढ़ी है। इसी दिशा में बागवानी उत्पादन किसानों के लिए आय बढ़ाने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने का एक प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है। फल, सब्जियां, फूल, मसाले, औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती आज कृषि क्षेत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है।

भारत की जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियां बागवानी फसलों के लिए अत्यंत अनुकूल हैं। देश के विभिन्न राज्यों में आम, केला, अमरूद, संतरा, सेब, अंगूर, अनार, आलू, प्याज, टमाटर और अनेक प्रकार की सब्जियों का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त फूलों की खेती और मसाला उत्पादन भी किसानों को बेहतर आर्थिक अवसर प्रदान कर रहे हैं। बागवानी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें कम भूमि पर भी बेहतर उत्पादन और अधिक मूल्य प्राप्त करने की संभावनाएं रहती हैं। यही कारण है कि छोटे और सीमांत किसान भी इस क्षेत्र को अपनाकर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकते हैं।

बागवानी उत्पादन का महत्व केवल किसानों की आय तक सीमित नहीं है। इसका सीधा संबंध पोषण, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और औद्योगिक विकास से भी है। फल और सब्जियां मानव शरीर को आवश्यक विटामिन, खनिज और पोषक तत्व उपलब्ध कराती हैं। बढ़ती आबादी और बदलती जीवनशैली के कारण पौष्टिक खाद्य पदार्थों की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में बागवानी क्षेत्र देश की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

हालांकि, इस क्षेत्र के सामने कई चुनौतियां भी हैं। फल और सब्जियां जल्दी खराब होने वाली उपज हैं। पर्याप्त शीतगृह, कोल्ड चेन, प्रसंस्करण इकाइयों और आधुनिक परिवहन सुविधाओं के अभाव में किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। कई बार बाजार में अधिक उत्पादन होने पर कीमतें इतनी गिर जाती हैं कि किसानों की लागत भी नहीं निकल पाती। इसके अलावा गुणवत्तापूर्ण बीज, पौध सामग्री, सिंचाई, आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक जानकारी की कमी भी उत्पादन को प्रभावित करती है। इन समस्याओं के समाधान के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को बागवानी क्षेत्र के विकास पर विशेष ध्यान देना होगा। किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक, ड्रिप सिंचाई, पॉलीहाउस, ग्रीनहाउस और जैविक खेती के प्रति प्रोत्साहित करना आवश्यक है।

कागजों पर साकार नहीं होता स्वच्छ गांव का सपना

हिमानी थायत, बागेश्वर

स्वच्छ गांव की तस्वीर केवल साफ-सुथरी गलियों और दीवारों पर लिखे स्वच्छता संदेशों से नहीं बनती। इसके लिए जरूरी है कि घर से निकलने वाला कचरा नियमित रूप से उठे, उसे रखने की जगह हो, गीले और सूखे कचरे को अलग करने की व्यवस्था हो और उसे सुरक्षित तरीके से निस्तारित किया जाए। जब गांव में यह व्यवस्था नहीं होती तो कचरा केवल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है और आखिरकार नालियों, खेतों, रास्तों या जल स्रोतों के आसपास जमा होने लगता है।

उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के मैगड़ी स्टेट गांव की कहानी इसी अधूरी व्यवस्था की ओर ध्यान खींचती है। पहाड़ों की हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता के बीच बसे इस गांव में कचरे की समस्या ग्रामीणों के लिए रोजमर्रा की परेशानी बन चुकी है। बागेश्वर से करीब 42 किमी दूर स्थित इस गांव की आबादी लगभग 1566 है और यहां करीब 320 परिवार रहते हैं। ग्रामीणों के अनुसार गांव में कूड़ा उठाने के लिए नियमित वाहन नहीं आता। नतीजा यह है कि लोग अपने स्तर पर कचरे को एक जगह इकट्ठा करते हैं, कई बार उसे जला देते हैं या नालियों और आसपास के खाली स्थानों में फेंक देते हैं। बरसात के दिनों में स्थिति और खराब हो जाती है। पानी के साथ बहता कचरा खेतों और छोटे नालों तक पहुंचता है, जिससे केवल गांव की सफाई ही प्रभावित नहीं होती, बल्कि खेती, जलस्रोतों और आसपास के पर्यावरण पर भी असर पड़ता है।

इस संबंध में 45 वर्षीय खष्टी देवी भी पुष्टि करती हैं कि गांव में कूड़े की गाड़ी नहीं आती, इसलिए लोग कचरे को एक जगह जमा करके जला देते हैं। उनके अनुसार आसपास के इलाकों में भी लोग कचरे को नदी-नालों में फेंक देते हैं। वह कहती हैं कि जब कचरा संग्रहण की व्यवस्था उपलब्ध नहीं होती है तो लोगों से केवल स्वच्छता की जिम्मेदारी निभाने की अपेक्षा करना उचित नहीं है। इसके लिए जरूरी बुनियादी व्यवस्था भी मौजूद हो। स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के दूसरे चरण में भी ठोस और तरल कचरा प्रबंधन को ग्रामीण स्वच्छता का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है। सरकार के अनुसार गांवों में कचरा संग्रहण, उसका अलगाव, परिवहन, कंपोस्टिंग, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन और अन्य स्थानीय



व्यवस्थाओं के लिए प्रावधान किए गए हैं। यहां तक कि ग्राम पंचायतों को कचरा संग्रहण और निस्तारण की व्यवस्था स्थापित करने की जिम्मेदारी भी दी गई है।

फिर सवाल यह है कि व्यवस्था होने के बावजूद मैगड़ी स्टेट जैसे गांवों में कूड़े की गाड़ी क्यों नहीं पहुंचती? सरकारी आंकड़े बताते हैं कि जुलाई 2025 तक देश के 5.19 लाख से अधिक गांवों में ठोस कचरा प्रबंधन की व्यवस्था दर्ज की गई थी और 6.36 लाख से अधिक कचरा संग्रहण एवं परिवहन वाहन उपलब्ध बताए गए थे।

यह निश्चित रूप से एक बड़ा विस्तार है, लेकिन ऐसे आंकड़ों की असली परीक्षा उन गांवों में होती है जहां व्यवस्था अभी भी ग्रामीणों के अनुभव का हिस्सा नहीं बन पाई है। मैगड़ी स्टेट की समस्या केवल कूड़े की गाड़ी तक सीमित नहीं है। गांव में मौजूद एकमात्र कूड़ेदान भी सड़क से दूर है। ग्रामीण बताते हैं कि वहां तक पहुंचने के लिए चढ़ाई पार करनी पड़ती है। बुजुर्गों और महिलाओं के लिए यह दूरी और कठिन हो जाती है। 65 वर्षीय पन्ना देवी का कहना है कि गाँव में सड़क नहीं होने के कारण कूड़े की गाड़ी नहीं आती है। यदि गांव के भीतर सड़क पहुंच जाए तो कचरे की गाड़ी घरों तक आ सकती है। गांव में स्वच्छता का सबसे बड़ा भार अक्सर उन्हीं लोगों पर पड़ता है जो रोजमर्रा के घरेलू कामों की जिम्मेदारी संभालते हैं।

महिलाओं को घर का कचरा बाहर ले जाना, पानी और बच्चों की देखभाल के साथ घर के आसपास की सफाई बनाए रखना पड़ता है। जब कूड़ेदान दूर हो और कचरा संग्रहण की नियमित व्यवस्था न हो तो यह अतिरिक्त जिम्मेदारी भी उन्हीं के हिस्से आती है। बुजुर्ग महिलाओं के लिए चढ़ाई चढ़कर कचरा ले जाना केवल असुविधा नहीं, बल्कि शारीरिक परेशानी का कारण भी बन सकता है। इसलिए ग्रामीण स्वच्छता की योजना बनाते समय यह देखना जरूरी है कि सुविधा वास्तव में गांव के हर व्यक्ति के लिए कितनी सुलभ है। हालांकि इस गांव को स्वच्छ बनाने में यहां की किशोरियों और महिलाओं की भूमिका सराहनीय है। नाममात्र संसाधन के बावजूद वह अपने आसपास के पर्यावरण को साफ रखने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनकी कोशिशों को व्यवस्था का साथ मिलना जरूरी है। स्वच्छता का संदेश तभी प्रभावी होगा जब गांव की महिला को यह महसूस हो कि उसके घर से निकला कचरा उसके रास्ते में, नाली में या खेत में वापस नहीं लौटेगा। जब उन्हें कचरा फेंकने के लिए घर से बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा और जब बारिश में कचरा बहकर खेतों और जलस्रोतों तक नहीं पहुंचेगा, तभी स्वच्छता लोगों के जीवन का हिस्सा बनेगी।

इस समस्या का एक दूसरा पहलू जागरूकता का भी है। ग्रामीणों में से कुछ लोगों को स्वच्छ भारत मिशन के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है। कुछ घरों में कूड़ेदान दिए जाने के बाद भी कचरा नालियों में फेंकने की बात सामने आती है। लेकिन केवल लोगों को दोष देने से समस्या हल नहीं होगी। यदि घर से कचरा अलग करने की सलाह दी जाती है तो उसके बाद उसे उठाने, छांटने और निस्तारित करने की व्यवस्था भी होनी चाहिए, क्योंकि स्वच्छता एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें किसी एक कड़ी के कमजोर पड़ने पर पूरी व्यवस्था प्रभावित होती है।

मैगड़ी स्टेट की कहानी किसी एक गांव की समस्या भर नहीं है। यह उस सवाल की ओर इशारा करती है जो ग्रामीण भारत के सामने अभी भी खड़ा है कि क्या स्वच्छता केवल लोगों के व्यवहार बदलने से आएगी या उसके लिए ऐसी स्थानीय व्यवस्था भी बनेगी जो लोगों को स्वच्छ रखने में सक्षम बनाए? यह सच है कि स्वच्छ भारत मिशन ने देश में स्वच्छता को एक बड़े जन-अभियान का रूप दिया है। लेकिन अब अगला कदम उस अभियान की पहुंच को गांव के आखिरी छोड़ तक पहुंचाने की जरूरत है।

भारत की राजनीति में आरोप नही प्रमाण की जरूरत

कांतिलाल मांडोत

भारतीय लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनो की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार के कामकाज पर सवाल उठाना विपक्ष का अधिकार ही नहीं, बल्कि उसकी जिम्मेदारी भी है। लेकिन सवाल उठाने और आरोप लगाने के बीच एक बड़ा अंतर होता है। किसी भी राजनीतिक दल को जनता के सामने अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, मगर उस बात के समर्थन में ठोस प्रमाण भी होने चाहिए। केवल भाषणों, नारों और आरोपों से न तो लोकतंत्र मजबूत होता है और न ही जनता का विश्वास जीता जा सकता है। कांग्रेस और राहुल गांधी के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वे अपनी राजनीति को आरोपों से निकालकर तथ्यों और जनहित के मुद्दों तक लेकर आएं।

हाल ही में हैदराबाद में आयोजित कांग्रेस के भारत समिट ने एक बार फिर देश की राजनीति में बहस छेड़ दी है। इस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने चुनावी व्यवस्था, लोकतांत्रिक संस्थाओं और वर्ष 2014 के बाद की राजनीति पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 2014 में भारत में लोकतंत्र को नष्ट कर दिया गया था। उनका यह भी कहना था कि राजनीतिक व्यवस्था में भारी मात्रा में पैसा लगाया गया और विपक्ष उस समय सदमे में था। उन्होंने सत्य और अहिंसा को कांग्रेस के दो प्रमुख हथियार बताते हुए वर्तमान, भूतकाल और भविष्य की लड़ाई लड़ने की बात कही। लोकतंत्र में राहुल गांधी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन जब कोई नेता देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर इतना गंभीर आरोप लगाता है तो उससे अपेक्षा होती है कि वह जनता के सामने ठोस प्रमाण भी रखे। केवल यह कह देना कि लोकतंत्र खत्म हो गया है, पर्याप्त नहीं है। यदि चुनावी व्यवस्था में गड़बड़ी है तो उसका विवरण, तथ्य और प्रमाण सामने आने चाहिए। जनता को भी यह समझना जरूरी है कि आरोप राजनीतिक भाषण का हिस्सा हैं या वास्तव में किसी गंभीर अनियमितता का प्रमाण।

भारत समिट में विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधियों की मौजूदगी को लेकर भी भाजपा नेताओं ने सवाल उठाए। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने पूछा कि कांग्रेस ऐसे लोगों को अपने राजनीतिक मंच पर क्यों जगह दे रही है, जिनके संबंध जॉर्ज सोरोस समर्थित ओपन सोसायटी नेटवर्क और एमनेस्टी इंटरनेशनल से जुड़े बताए जाते हैं। उन्होंने इक्वाडोर के पूर्व मंत्री गुइलेर्मो लांग और एमनेस्टी इंटरनेशनल के पूर्व महासचिव सलिल शेट्टी का उल्लेख करते हुए उनकी पृष्ठभूमि और भारत से जुड़े पुराने बयानों पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि इन लोगों को मंच देने के पीछे उसका उद्देश्य क्या है। भाजपा नेता सीआर केसवन ने भी सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस के प्रायोजित भारत समिट में राहुल गांधी और उनके सहयोगियों ने देश तथा लोकतंत्र के बारे में अपमानजनक बातें कहीं। उन्होंने कार्यक्रम में शामिल कुछ विदेशी प्रतिनिधियों की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इटली के नेता जियाकोमो फिलिबेक के भाषण का वीडियो सामने आने के बाद राहुल गांधी पर निशाना साधा। फिलिबेक ने अपने भाषण में कांग्रेस का नारा 'वोट चोर गद्दी छोड़' लगाया था। वीडियो में राहुल गांधी तालियां बजाते दिखाई दिए। इस पर रिजिजू ने सवाल किया कि जब कोई विदेशी व्यक्ति भारत का अपमान करता है तो उस समय कौन हंसता है?

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने भी विदेशी प्रतिनिधियों के सामने देश के आंतरिक राजनीतिक मुद्दे उठाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने मतदाता सूची से नाम हटाने के राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि मृत व्यक्तियों, दोहरे मतदाताओं और स्थायी रूप से दूसरी जगह जा चुके लोगों के नाम हटाना आवश्यक है। मतदाता सूची की शुद्धता लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है। यदि किसी वास्तविक मतदाता का नाम गलत तरीके से हटाया गया है तो उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन पूरी प्रक्रिया को ही गलत बताना उचित नहीं है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुणे में आयोजित कार्यक्रम में राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय मंचों से भारत को बदनाम करके सत्ता हासिल नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को विदेश यात्राओं के बजाय गांव-गांव जाकर जनता से जुड़ना चाहिए। शाह ने कांग्रेस की लगातार चुनावी हार का उल्लेख करते हुए कहा कि पार्टी अपना राजनीतिक असंतोष अलग-अलग तरीकों से निकाल रही है। उन्होंने कृषि, उद्योग, रेलवे, हवाई अड्डों, मेट्रो, अंतरिक्ष अनुसंधान और नई शिक्षा नीति जैसे क्षेत्रों में पिछले वर्षों में हुए विकास कार्यों का भी उल्लेख किया। शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास की नई दिशा पकड़ी है और उन पर भ्रष्टाचार का कोई ठोस आरोप साबित नहीं हुआ है।

कांग्रेस के लिए इन राजनीतिक सवालों में एक बड़ी सीख छिपी है। जनता केवल भाषण सुनकर अपना निर्णय नहीं करती। वह सरकार के काम, नेताओं के व्यवहार और उनके दावों की सच्चाई भी देखती है। कांग्रेस को यह समझना होगा कि उसकी कथनी और करनी में अंतर दिखाई देने लगे तो जनता का भरोसा कमजोर होता है। बार-बार बड़े आरोप लगाने से पहले उन्हें प्रमाणों के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। झूठ और अधूरे तथ्यों का पुलिंदा लंबे समय तक नहीं चल सकता।

राजनीति में विश्वसनीयता सबसे बड़ी पूंजी होती है। आज का युवा, विशेषकर नई पीढ़ी, रोजगार, शिक्षा, तकनीक, अवसर और देश के भविष्य को लेकर गंभीर है। वह केवल राजनीतिक नारे नहीं सुनना चाहता, बल्कि यह जानना चाहता है कि उसके जीवन में सुधार के लिए कौन क्या कर रहा है। यदि राजनीति का केंद्र केवल विरोध और आरोप बन जाएगा तो युवा उससे दूरी बना सकता है। राहुल गांधी को यह समझना होगा कि सरकार का विरोध करते-करते देश की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली भाषा से बचना भी उतना ही जरूरी है। देश की कमियों पर सवाल उठाना देशविरोध नहीं है, लेकिन आलोचना तथ्यों और जिम्मेदारी के साथ होनी चाहिए।

कांग्रेस का जनाधार कमजोर होने के पीछे भी आत्ममंथन की आवश्यकता है। पार्टी को यह देखना होगा कि जनता उससे क्यों दूर हो रही है। केवल भाजपा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार को निशाना बनाने से राजनीतिक भविष्य नहीं बन सकता। देश की जनता को विकास, सुरक्षा, रोजगार, सामाजिक सद्भाव और मजबूत नेतृत्व चाहिए। धर्म, समाज और राष्ट्रीय पहचान को लेकर विवादित टिप्पणियां करने के बजाय सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की जरूरत है।

राजनीति में विरोध होना चाहिए, लेकिन विरोध का उद्देश्य देश को कमजोर करना नहीं, बल्कि व्यवस्था को बेहतर बनाना होना चाहिए। भारत की जनता ने हमेशा उन नेताओं को महत्व दिया है जो कठिन परिस्थितियों में उसके साथ खड़े रहे, गांवों तक पहुंचे और विकास के लिए काम किया। जनता से जुड़ने वाला नेता ही उसकी अपेक्षाओं को समझ सकता है। सत्ता का रास्ता विदेशी मंचों पर भाषण देने या केवल नैरेटिव बनाने से नहीं, बल्कि देश के करोड़ों लोगों का विश्वास जीतने से निकलता है। लोकतंत्र में अंतिम फैसला जनता करती है और जनता के फैसले का सम्मान करना ही सच्ची लोकतांत्रिक भावना है।

भाजपा साध रही परिसीमन और महिला आरक्षण पर दोहरा निशाना

डॉ. ज्ञान पाठक

'इंडिया' गठबंधन को भाजपा की इस रणनीति के बारे में पहले से पता है। वे संसद में इन बिलों को एकजुट होकर हराने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और साथ ही उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में भाजपा की चाल को भी नाकाम करने के लिए तैयार हैं। डीएमके, एनसीपी (शरद पवार) और सपा के क्षेत्रीय हित, कांग्रेस के राष्ट्रीय हितों से अलग हैं।

भरतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने संसद के विशेष सत्र की योजना बनायी है ताकि संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और महिला आरक्षण बिल फिर लाया जाये, जिस पर चर्चा भी तेज कर दी गयी है। हालांकि भाजपा के पास लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत नहीं है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कथित तौर पर कहा है कि ये विधेयक 15-18 वोटों के अंतर से पारित हो जाएंगे।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने 12 नवंबर को सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, 'गृह मंत्री ने आज पत्रकारों के एक समूह से अनौपचारिक बातचीत के दौरान 'परिसीमन' के मुद्दे को फिर से हवा दी है। उन्होंने आज दोपहर बताया कि जल्द ही संसद का 3 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया जाएगा और ये बिल 15-18 वोटों के अंतर से पारित कर दिए जाएंगे।' रमेश ने आगे कहा, 'उन्होंने सात महीने पहले भी यही बात कही थी, लेकिन 17 अप्रैल को लोकसभा में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा था, जहां वे बहुमत के आंकड़े से 50 से अधिक वोट पीछे रह गए थे। वे सिर्फ डींगें हांकने और झांसा देने में माहिर हैं। उनका बुलडोजर तब भी काम नहीं आया था और आगे भी काम नहीं आएगा।'

13 अगस्त को संसद के मानसून सत्र के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद से ही विशेष सत्र बुलाए जाने की अटकलें लगाई जा रही थीं, क्योंकि सत्र का सत्रावसान नहीं किया गया था। इससे यह कयास लगाए जाने लगे कि सरकार विवादित बिलों को पारित कराने के लिए विशेष सत्र बुला सकती है–वही बिल जो बजट सत्र के दौरान पारित नहीं हो पाए थे। चूंकि सत्र का सत्रावसान नहीं हुआ है, इसलिए केवल दो दिन के नोटिस पर विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। वहीं, शीतकालीन सत्र 30 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच शुरू होने की संभावना है, जिसके लिए 14 दिन के नोटिस की आवश्यकता होती है।

हालांकि विशेष सत्र की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन मीडिया में यह मान लिया गया है कि यह सत्र आयोजित होगा–भले ही सरकार इन बिलों को पारित कराने में सफल हो या न हो। भाजपा के इस आक्रामक रुख के पीछे दो मुख्य लक्ष्य हैं। पहला, बिल पास कराने के लिए जरूरी संख्या जुटाना। दूसरा, विपक्ष की उस एकजुटता को कमजोर करना जो उन्होंने हाल ही में सीईसी और एसआईआर से जुड़े आंदोलनों के दौरान दिखाई थी। इसके अलावा, इसका एक मकसद 2027 की शुरुआत में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों को प्रभावित करना भी है। उत्तर प्रदेश से लोकसभा में सबसे ज्यादा सांसद चुनकर आते हैं, और केंद्र की सत्ता काफी हद तक इसी राज्य पर निर्भर करती है।

ऐसी खबरें हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिसीमन और महिला आरक्षण बिल पर समर्थन पाने के लिए डीएमके और शरद पवार की एनसीपी को कैबिनेट में जगह देने का प्रस्ताव दिया है। इससे पहले, इन दोनों पार्टियों ने संकेत दिया था कि वे परिसीमन बिल का समर्थन कर सकती हैं, बशर्ते उनके राज्यों–तमिलनाडु और महाराष्ट्र–के हितों की रक्षा की जाए। हालांकि, दोनों पार्टियां एक मुश्किल स्थिति में हैं। वे शायद ही कैबिनेट में कुछ सीटों के लिए अपनी पूरी राजनीतिक पहचान और भविष्य को दांव पर लगाना चाहें, खासकर तब जब इससे केवल भाजपा के राजनीतिक हितों को ही फायदा पहुंचे।

भाजपा को यह बात पता है, लेकिन वह लगातार यह आख्यान आगे बढ़ रही है कि उनके पास पर्याप्त बहुमत है और वे 15-18 सीटों के अंतर से बिल पास करा लेंगे। यह दावा विश्वसनीय नहीं लगता, क्योंकि 543 सदस्यों वाली लोकसभा में एनडीए के पास केवल 319 सांसद हैं, और 250 सदस्यों वाली राज्यसभा में सिर्फ 154 सांसद हैं। लोकसभा में अभी तीन सीटें खाली हैं, इसलिए भाजपा को बिल पास कराने के लिए लोकसभा में 360 और राज्यसभा में 163 वोटों की जरूरत होगी।

सटीक जनसंख्या आँकड़ों के बिना नीतियों की सफलता अधूरी

डॉक्टर सत्यवान सौरभ

लोकतंत्र में शासन की सफलता केवल योजनाएँ बनाने और बजट आवंटित करने से सुनिश्चित नहीं होती, बल्कि इस बात से तय होती है कि सरकार की नीतियाँ समाज की वास्तविक आवश्यकताओं को कितना समझती हैं। किसी देश की जनसंख्या कितनी है, उसमें बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों, युवाओं और विभिन्न सामाजिक समूहों की हिस्सेदारी क्या है, कितने लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और कितने शहरी क्षेत्रों में, कितने परिवार गरीबी, अशिक्षा तथा बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझ रहे हैं–इन सभी प्रश्नों का व्यवस्थित उत्तर जनगणना से मिलता है। इसलिए जनगणना केवल लोगों की गिनती करने की प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक वास्तविकताओं को समझने का सबसे व्यापक माध्यम है।

भारत जैसे विशाल, विविधतापूर्ण और बहुस्तरीय समाज में विश्वसनीय जनगणना आँकड़ों का महत्त्व और भी बढ़ जाता है। वर्ष 2011 के बाद प्रस्तावित जनगणना 2027 इसलिए ऐतिहासिक महत्त्व रखती है, क्योंकि इसके माध्यम से देश को लंबे अंतराल के बाद नई जनसांख्यिकीय तस्वीर प्राप्त होगी। डिजिटल तकनीक, ऑनलाइन डेटा संग्रह और वास्तविक समय में निगरानी जैसी व्यवस्थाएँ इस प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम हैं। लेकिन तकनीक का इस्तेमाल तभी सार्थक होगा, जब आँकड़ों की शुद्धता, निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित हो।

विश्वसनीय जनगणना का पहला और सबसे महत्त्वपूर्ण पक्ष कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन है। भारत में खाद्य सुरक्षा, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी अनेक योजनाएँ जनसंख्या संबंधी आँकड़ों पर निर्भर करती हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान हो या प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवासीय आवश्यकताओं का आकलन, सटीक आँकड़े नीति निर्माण की बुनियाद तैयार करते हैं। यदि जनगणना में किसी क्षेत्र की आबादी कम दर्ज होती है, तो वहाँ वास्तविक आवश्यकता के अनुपात में संसाधन नहीं पहुँच पाते। इसका सबसे अधिक नुकसान गरीबों, प्रवासी श्रमिकों, बेघर लोगों और वंचित समुदायों को उठाना पड़ता है।

दूसरा महत्त्वपूर्ण पक्ष संसाधनों का न्यायसंगत वितरण है। सरकार को यह तय करना होता है कि कहाँ नए विद्यालय खोले जाएँ, किन क्षेत्रों में अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की आवश्यकता है, कहाँ सड़क, पेयजल और परिवहन सुविधाओं का विस्तार किया जाए तथा किस क्षेत्र में रोजगार और कौशल विकास कार्यक्रमों को प्राथमिकता मिले। उदाहरण के लिए, तेजी से बढ़ती शहरी आबादी वाले क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन, आवास और स्वच्छता सुविधाओं की माँग अधिक होती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं, कृषि आधारित आधारभूत संरचना और शिक्षा की विशेष आवश्यकता हो सकती है। जनगणना के विश्वसनीय आँकड़े इन प्राथमिकताओं को निर्धारित करने में सहायता करते हैं।

जनगणना का लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व से भी गहरा संबंध है। लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया में जनसंख्या संबंधी आँकड़ों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। जनसंख्या में होने वाले बदलावों को समझे बिना राजनीतिक प्रतिनिधित्व में संतुलन स्थापित करना कठिन है। इसी प्रकार वित्त आयोग को राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण संबंधी सिफारिशें तैयार करने में जनसांख्यिकीय तथ्यों सहित अनेक मानकों का सहारा लेना पड़ता है। इस प्रकार जनगणना के आँकड़े केवल प्रशासनिक सुविधा नहीं, बल्कि संघीय व्यवस्था और लोकतांत्रिक संतुलन के भी आधार हैं। हालाँकि, विश्वसनीय जनगणना सुनिश्चित करना आसान कार्य नहीं है। भारत की भौगोलिक विविधता, विशाल जनसंख्या, सामाजिक विषमताएँ और तेजी से बदलती जीवनशैली इसके सामने अनेक चुनौतियाँ प्रस्तुत करती हैं। सबसे बड़ी चुनौती जनसंख्या की सही गणना सुनिश्चित करना है। प्रवासी श्रमिक, बेघर नागरिक, घुमंतू समुदाय, दूरदराज के आदिवासी समूह और अस्थायी रूप से रहने वाले लोग अक्सर गणना की प्रक्रिया से छूट सकते हैं। महानगरों में काम की तलाश में आने वाले श्रमिकों का निवास अस्थायी होता है। ऐसे लोगों की सही गणना और उपयुक्त स्थान पर उनका पंजीकरण एक जटिल प्रशासनिक चुनौती है। यदि ये समूह आँकड़ों से बाहर रह जाते हैं, तो उनकी वास्तविक समस्याएँ भी नीतिगत प्राथमिकताओं में पीछे छूट सकती हैं।

दूसरी चुनौती डिजिटल असमानता है। जनगणना में मोबाइल एप्लीकेशन, डिजिटल उपकरणों और ऑनलाइन निगरानी का उपयोग प्रक्रिया को तेज तथा व्यवस्थित बना सकता है, लेकिन देश के सभी क्षेत्रों में डिजिटल सुविधाएँ समान रूप से उपलब्ध नहीं हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी, बिजली की अनियमित आपूर्ति, तकनीकी उपकरणों की अनुपलब्धता और डिजिटल साक्षरता का अभाव दूरस्थ ग्रामीण एवं पहाड़ी क्षेत्रों में कठिनाइयाँ पैदा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, तकनीकी प्रणाली में गड़बड़ी या डेटा अपलोड करने में त्रुटि भी आँकड़ों की गुणवत्ता प्रभावित कर सकती है। तीसरी चुनौती मानवीय और प्रशासनिक त्रुटियों से जुड़ी है। जनगणना का बड़ा हिस्सा गणनाकर्मियों द्वारा घर-घर जाकर जानकारी एकत्र करने पर आधारित होता है। यदि गणनाकर्मियों को पर्याप्त प्रशिक्षण न मिले या प्रश्नों की व्याख्या में एकरूपता न हो, तो गलत जानकारी दर्ज हो सकती है। कई बार उत्तरदाता भी सामाजिक संकोच, जानकारी के अभाव अथवा सरकारी लाभ प्रभावित होने की आशंका के कारण सही जानकारी देने से बचते हैं। भाषा, स्थानीय बोलियों और सामाजिक परिस्थितियों की विविधता इस समस्या को और जटिल बनाती है।

इसके साथ ही निजता और व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा का प्रश्न भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। डिजिटल युग में नागरिकों के मन में यह आशंका हो सकती है कि उनके द्वारा दी गई व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग किया जाएगा। यदि लोगों को यह विश्वास नहीं होगा कि उनकी जानकारी सुरक्षित और गोपनीय रहेगी, तो वे जनगणना में सहयोग करने से हिचक सकते हैं। इसलिए डेटा सुरक्षा केवल तकनीकी विषय नहीं, बल्कि जनगणना की विश्वसनीयता से जुड़ा सामाजिक और लोकतांत्रिक प्रश्न भी है। इन चुनौतियों के समाधान के लिए सबसे पहले गणनाकर्मियों का व्यापक और व्यावहारिक प्रशिक्षण आवश्यक है। उन्हें स्थानीय भाषा, सामाजिक संरचना, प्रश्नावली और डिजिटल उपकरणों के इस्तेमाल की समुचित जानकारी दी जानी चाहिए।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक विजय कुमार द्वारा ओ.एस. पब्लिकेशन, बी-2542, नरेला, इंडस्ट्रियल एरिया, नार्थ वेस्ट दिल्ली-110040 से मुद्रित कराकर 1536/108 गणेशपुरा रोड, त्रीनगर दिल्ली-110035 से प्रकाशित। सम्पादक : विजय कुमार RNI No. : DELHIN/2015/66886
अखबार में प्रकाशित तथ्यों एवं लेखों से सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं, किसी भी कानूनी वाद विवाद का निपटारा दिल्ली न्यायालय के अधीन होगा। मोबाइल : 9210092542 फोन :- 011-46696546 E-mail : opensearchdelhi@gmail.com

उत्तर प्रदेश में नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी! अब कुल 13.58 करोड़ मतदाता, 18 लाख से अधिक नए वोटर जुड़े

लखनऊ (एजेंसी)



मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने लोक भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुनरीक्षण अभियान के आंकड़े जारी करते हुए बताया कि नई ड्राफ्ट सूची में 7 करोड़ 38 लाख 58 हजार 510 पुरुष, 6 करोड़ 20 लाख 6 हजार 353 महिला और 4,042 तृतीय लिंग के मतदाता शामिल हैं। उन्होंने बताया कि 10 अप्रैल 2026 को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या के मुकाबले अब 18.84 लाख की बढ़ोतरी हुई है

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को दुरुस्त करने की कवायद तेज हो गई है। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत मंगलवार को प्रदेश की आलेख्य मतदाता सूची जारी कर दी गई। नई सूची में कुल 13 करोड़ 58 लाख 68 हजार 905 मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने लोक भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुनरीक्षण अभियान के आंकड़े जारी करते हुए बताया कि नई ड्राफ्ट सूची में 7 करोड़ 38 लाख 58 हजार 510 पुरुष, 6 करोड़ 20 लाख 6 हजार 353 महिला और 4,042 तृतीय लिंग के मतदाता शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि 10 अप्रैल 2026 को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या के मुकाबले अब 18.84 लाख की बढ़ोतरी हुई है। आंकड़ों के मुताबिक, इस अवधि में महिला मतदाताओं की संख्या में 10 लाख 96 हजार 828 की वृद्धि हुई जबकि पुरुष मतदाताओं की संख्या 7 लाख 87 हजार 449 बढ़ी है। वहीं, तृतीय लिंग के मतदाताओं की संख्या में 164 की कमी दर्ज की गई है। इस तरह मतदाता सूची में महिलाओं की भागीदारी में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि हुई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची में प्रति एक हजार पुरुष मतदाताओं पर महिला मतदाताओं की संख्या का अनुपात 834 से बढ़कर 840 हो गया है। इसी तरह मतदाता-जनसंख्या अनुपात भी 55.17 प्रतिशत से बढ़कर 55.95 प्रतिशत दर्ज किया गया है। निर्वाचन विभाग का कहना है कि पुनरीक्षण के दौरान पात्र नागरिकों को मतदाता सूची से जोड़ने के प्रयास किए गए हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक, 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग की अनुमानित आबादी 84 लाख 47 हजार है जबकि ड्राफ्ट मतदाता सूची में इस आयु वर्ग के महज 11.83 लाख मतदाताओं के नाम शामिल हैं। निर्वाचन विभाग ने इस अंतर को कम करने के लिए स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में विशेष अभियान चलाने की तैयारी की है, ताकि पात्र युवाओं को मतदाता सूची में शामिल कराया जा सके। आलेख्य मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ ही नाम जोड़ने, हटाने और विवरण में संशोधन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। नागरिक 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। इस दौरान नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6, मतदाता सूची से नाम हटवाने या किसी प्रविष्टि पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए फॉर्म-7 और नाम, पता अथवा अन्य विवरण में संशोधन के लिए फॉर्म-8 भरना होगा। निर्वाचन विभाग के कार्यक्रम के अनुसार, 28 दिसंबर तक प्राप्त दावों और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। इसके बाद चार जनवरी 2027 को प्रदेश की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। मतदाता सूची को अधिक समावेशी बनाने और पात्र नागरिकों को इसमें शामिल करने के लिए 21, 22, 28 और 29 नवंबर को प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष अभियान दिवस आयोजित किए जाएंगे। इन दिनों बूथ लेवल अधिकारी अपने-अपने बूथ पर आलेख्य मतदाता सूची और आवेदन फॉर्म के साथ मौजूद रहेंगे। नागरिक इनसे संपर्क कर सूची में अपना नाम और विवरण जांचने के साथ आवश्यक आवेदन भी कर सकेंगे। मतदाता अपने नाम और अन्य विवरणों की जांच संबंधित मतदान केंद्र, बीएलओ के पास उपलब्ध सूची, ईसीआईनेट मोबाइल ऐप और मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा भारत निर्वाचन आयोग के नागरिक सेवा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर भी मतदाता सूची उपलब्ध रहेगी।

यदि किसी पात्र नागरिक का नाम सूची में नहीं है तो वह फॉर्म-6 के माध्यम से नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकता है। इसके साथ निर्धारित फोटो और जन्मतिथि तथा सामान्य निवास से संबंधित मान्य दस्तावेज देने होंगे। वहीं, निवास स्थान बदलने, नाम-पते में सुधार, मतदाता पहचान पत्र से जुड़ी प्रविष्टियों में संशोधन अथवा दिव्यांग मतदाता के रूप में चिन्हांकन के लिए फॉर्म-8 का इस्तेमाल किया जा सकता है।

अखिलेश यादव कृष्ण जन्मभूमि के लिए आवाज उठाएं तो धुल जाएगा पुराना पाप : दिनेश शर्मा

मथुरा (एजेंसी)



उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बयान का समर्थन करते हुए मथुरा विवाद में हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता दिनेश शर्मा ने कहा कि अयोध्या का पांच सौ वर्ष पुराना सपना पूरा हो चुका है। अब सनातनियों की यही कामना है कि मथुरा का सपना भी साकार हो। जिस प्रकार अयोध्या में भव्य दरबार सजा है, उसी प्रकार मथुरा में भी दरबार सजना चाहिए।

दिनेश शर्मा ने कहा कि कृष्ण भक्तों की अब यही अभिलाषा है कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव आगे आएं और कृष्ण जन्मभूमि की आजादी के लिए आवाज उठाएं। उन्होंने कहा कि अयोध्या में सपा की सरकार के समय राम भक्तों पर गोली चलाई गई थी, यदि अखिलेश यादव कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के लिए आवाज उठाएंगे तो वह पाप धुल जाएगा। ऐसा करने पर सभी कृष्ण भक्त भी उनके साथ खड़े हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि उपमुख्यमंत्री केशव मौर्य भी अखिलेश यादव के साथ खड़े होने की बात कह रहे हैं। यह बहुत अच्छा मौका है। सभी सनातनियों को एकजुट होना चाहिए और कृष्ण मंदिर के लिए आवाज उठानी चाहिए। जब भी न्यायालय का फैसला आएगा, तो हम यही चाहते हैं कि यहां कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य मंदिर बने।

बता दें कि उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि यदि वे सच्चे कृष्ण भक्त या राम भक्त हैं और उन्हें मुस्लिम वोटों का लालच नहीं है, तो वे खुलकर सामने आएं और मथुरा में कारसेवा के लिए साथ आएं।

प्रयागराज : गोपाष्टमी पर बलुआ घाट पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, गौ माता की हुई पूजाा

प्रयागराज (एजेंसी)



कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की गोपाष्टमी के पावन अवसर पर मंगलवार को प्रयागराज के बलुआ घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही यमुना तट पर भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। महिलाओं ने पारंपरिक परिधान में सज-धजकर घाट पर पहुंचकर पूजा-अर्चना की। पूरे घाट पर भक्ति और उल्लास का वातावरण बना रहा। गोपाष्टमी के दिन गाय की विशेष पूजा का विधान है। श्रद्धालुओं ने गौ माता की पूजा कर उन्हें माला पहनाई, तिलक लगाया और हरा चारा खिलाया। इसके साथ ही लड्डू गोपाल को माखन-मिश्री, दही और दूध का भोग लगाया गया। कई श्रद्धालुओं ने दही-पेड़े का भोग लगाकर उसका दान भी किया। घाट पर बने अस्थायी पूजा स्थलों पर महिलाओं ने एक साथ बैठकर सामूहिक रूप से पूजा की। बलुआ घाट पर आए पंडित महेंद्र मिश्रा ने इस पर्व के धार्मिक महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मंगलवार को कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की गोपाष्टमी है।

इस दिन गाय की पूजा होती है और लड्डू गोपाल को माखन-मिश्री तथा दही का भोग लगाया जाता है। कुछ लोग दूध का भी भोग लगाते हैं। उन्होंने कहा कि इसी पर्व के कारण यमुना के बलुआ घाट पर काफी भीड़ है। श्रद्धालु आ रहे हैं, गाय की पूजा कर रहे हैं और सभी रस्मों को निभा रहे हैं। श्रद्धालु राजरानी जायसवाल ने भी इस पर्व को लेकर अपनी आस्था व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कार्तिक माह में गोपाष्टमी का विशेष महत्व है। आज के दिन भगवान को दही-पेड़े का भोग लगता है और गोपाष्टमी मनाई जाती है। उन्होंने कहा कि हम सभी सखियां यहां आकर पूजा-अर्चना करती हैं और इससे बहुत आनंद मिलता है। उन्होंने अपनी कामना व्यक्त करते हुए कहा कि भगवान बाल-बच्चों को बनाए रखें, सभी सखियों में प्रेम बना रहे और यमुना मैया की कृपा इसी तरह बनी रहे। सभी का शरीर स्वस्थ रहे, ताकि लोग हर साल मां के चरणों में आकर सिर झुकाते रहें। वहीं, श्रद्धालु रेनू ने कहा कि आज गोपाष्टमी है। कार्तिक महीने की इस गोपाष्टमी पर गौ माता की सेवा की जाती है, उनकी पूजा-अर्चना की जाती है और दही-पेड़े का भोग लगाया जाता है। दही-पेड़े का दान भी किया जाता है। उन्होंने कहा कि हम लोगों की यही कामना है कि माता रानी हमें ऐसे ही अपने चरणों में स्थान देती रहें और हमें बुलाती रहें। हमें स्वस्थ रखें, परिवार हरा-भरा बना रहे और सुख-समृद्धि बनी रहे।

पीडीए सिर्फ नारा, हकीकत में पिछड़ों-दलितों को सपा ने किया नजरअंदाज : दानिश अंसारी

लखनऊ (एजेंसी)



उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच प्रदेश सरकार के राज्यमंत्री दानिश आजाद अंसारी ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर प्रदेश के विकास में बाधा डालने का आरोप लगाया।

साथ ही, उन्होंने सपा के पीडीए के नारे पर भी सवाल उठाए। दानिश आजाद अंसारी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा ने हमेशा पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदायों को धोखा देने का काम किया है। पार्टी इन वर्गों के हितों की वकालत करने का दावा तो करती है लेकिन उसकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। सपा के पिछले कार्यकाल और उसके राजनीतिक फैसलों को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि पार्टी की कथनी और वास्तविक कार्यशैली में काफी अंतर रहा है। दानिश अंसारी ने सपा के पीडीए नारे पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब पार्टी के पास राज्यसभा में दो सदस्यों को भेजने का अवसर था, तब उसे पिछड़े, दलित या अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधियों को प्राथमिकता देनी चाहिए थी लेकिन पार्टी ने इन वर्गों के हितों को महत्व नहीं दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा को उस समय पिछड़े और दलित समाज की चिंता नहीं थी और मुस्लिम समुदाय के कल्याण के प्रति भी उसकी प्रतिबद्धता वास्तविक नहीं रही। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर हुई बैठक पर प्रतिक्रिया देते हुए दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि विपक्षी गठबंधन की बैठकों का कोई सार्थक उद्देश्य नहीं है।

जेवर में साइड देने को लेकर दो पक्षों में खूनी संघष, 3 लोगों को लगी गोली, अस्पताल में भर्ती

ग्रेटर नोएडा (एजेंसी)



गौतमबुद्धनगर के जेवर थाना क्षेत्र में गाड़ी को साइड देने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट और फायरिंग तक पहुंच गया। बांकापुर गांव की नहर पटरी पर स्कॉर्पियो और थार सवार लोगों के बीच हुई कहासुनी के बाद दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। इस दौरान कथित तौर पर जमकर फायरिंग की गई, जिसमें तीन लोगों को गोली लगने की सूचना है। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, घटना जेवर थाना क्षेत्र के बांकापुर नहर पटरी की है। बताया जा रहा है कि प्रथम पक्ष के लोग ग्राम बांकापुर के निवासी हैं और स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार थे। वहीं, दूसरा पक्ष ग्राम गढ़ी का रहने वाला है और थार वाहन में सवार था। दोनों पक्षों के बीच सड़क पर साइड देने और गाड़ी हटाने को लेकर कहासुनी शुरू हुई थी। देखते ही देखते मामूली विवाद ने गंभीर रूप ले लिया और दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हो गया। आरोप है कि विवाद के दौरान दोनों पक्षों की ओर से फायरिंग की गई।

इस घटना में तीन लोगों को गोली लगने की जानकारी सामने आई है। वहीं, पुलिस के आधिकारिक बयान के अनुसार, घटना में एक पक्ष के दो और दूसरे पक्ष के तीन लोगों सहित कुल पांच व्यक्तियों को स्थानीय पुलिस ने अपनी निगरानी में उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। सभी घायलों की स्थिति सामान्य बताई गई है। घटना की सूचना मिलने के बाद जेवर थाना पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने के साथ ही दोनों पक्षों के बीच हुए विवाद की जानकारी जुटाई। प्रारंभिक जांच में विवाद की वजह गाड़ी को साइड देने को लेकर हुआ झगड़ा सामने आया है। पुलिस दोनों पक्षों के लोगों से पूछताछ कर रही है और घटना के दौरान फायरिंग किए जाने के आरोपों की भी जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक, मामले में तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। घटना में शामिल लोगों की भूमिका की जांच के साथ ही विवाद के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस की निगरानी में सभी घायल अस्पताल में उपचाराधीन हैं और उनकी हालत सामान्य है। दिनदहाड़े सड़क पर साइड देने जैसे मामूली विवाद के बाद फायरिंग की घटना ने एक बार फिर क्षेत्र में कानून-व्यवस्था और आपसी विवादों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

बिहार : छठ की तैयारियों के बीच 4 साल की बच्ची से कुकर्म का प्रयास, आरोपी गिरफ्तार

बक्सर (एजेंसी)

बिहार के बक्सर में छठ महापर्व के दौरान चार साल की मासूम बच्ची के साथ कुकर्म के प्रयास का मामला सामने आया है। घटना नगर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले की है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर महिला थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

पुलिस ने बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार, रविवार रात मोहल्ले के लोग छठ महापर्व की तैयारियों और पूजा-पाठ में व्यस्त थे। इसी दौरान आरोपी ने कथित तौर पर चार साल की बच्ची के साथ गलत हरकत करने का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि बच्ची के शोर मचाने पर परिजनों और स्थानीय लोगों के पहुंचने की आशंका से आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। घटना के बाद 16 नवंबर को पीड़िता के परिजनों ने महिला थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई शुरू की। बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया गया और घटना से जुड़े तथ्यों की जांच की गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में सदर एसडीपीओ गौरव पांडेय ने बताया कि मामला संज्ञान में आते ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बच्ची के साथ कुकर्म के प्रयास का मामला सामने आया है। इस संबंध में पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है।

शादी समारोह में विवाद के बाद अंधाधुंध फायरिंग, दो मासूम भाइयों को लगी गोली, पांच साल के बच्चे की मौत

मधेपुरा (एजेंसी)



बिहार के मधेपुरा में शादी समारोह के बाद हुए विवाद ने दो मासूम बच्चों की जान खतरे में डाल दी। सोमवार रात एक युवक ने कथित तौर पर देसी कट्टे से फायरिंग कर दी। इसमें दो सगे भाइयों को गोली लग गई। हादसे में 5 साल के सरफराज की मौत हो गई, जबकि उसका 3 साल का भाई अली हुसैन गंभीर रूप से घायल है।

दोनों बच्चे अपने पिता के साथ ननिहाल में शादी समारोह में शामिल होने आए थे। घटना बिहारीगंज थाना क्षेत्र की जौतेली पंचायत के गुलाब टोला स्थित वार्ड नंबर 12 की है। जानकारी के अनुसार, सोमवार को गुलाब टोला निवासी मो. बिजल की बेटी की शादी थी। बारात चौसा थाना क्षेत्र के लौआलगान से आई थी। शादी की सभी रस्में पूरी होने के बाद दुल्हन की विदाई हो गई। इसके बाद घर के लोग आपस में बैठे हुए थे। इसी दौरान गांव के शेख इस्लाम का बेटा मो. औरंगजेब आलम देसी कट्टा लेकर वहां पहुंचा और फायरिंग करने लगा। बताया जा रहा है कि बारात के दौरान भी आरोपी बारातियों को हथियार दिखाकर डरा रहा था। उस समय लोगों ने उसे समझाकर वहां से हटा दिया था। ग्रामीणों के मुताबिक, सोमवार सुबह आरोपी का बच्चों के पिता के साथ भी विवाद हुआ था। आशंका जताई जा रही है कि इसी रंजिश में आरोपी ने रात में नशे की हालत में दोनों मासूम भाइयों पर गोली चला दी। फायरिंग में दोनों बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों ने आरोपी के नशे का आदी होने की बात भी कही है। गोली लगने के बाद परिजन आनन-फानन में दोनों बच्चों को स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) लेकर पहुंचे।

वहां चिकित्सकों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए मधेपुरा रेफर कर दिया। हालांकि, अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में 5 साल के सरफराज की मौत हो गई। वहीं, उसके 3 वर्षीय भाई अली हुसैन की हालत भी गंभीर बनी हुई है। मृतक की पहचान पूर्णिया जिले के भवानीपुर थाना क्षेत्र के रोशनगंज निवासी मो. सोनाजीर के बेटे मो. सरफराज (5) के रूप में हुई है। घायल बच्चे का नाम मो. अली हुसैन (3) है। जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. अंजनी कुमार ने बताया कि दोनों बच्चों को गोली लगी थी। इनमें से एक बच्चे को अस्पताल मृत अवस्था में लाया गया था, जबकि दूसरे की हालत भी चिंताजनक थी। प्राथमिक उपचार के बाद घायल बच्चे को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया।

उदाकिशुनगंज के एसडीपीओ पवन कुमार सिंह ने घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। पुलिस पूरे घटनाक्रम और फायरिंग के पीछे की वजह का पता लगा रही है। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी मामले की छानबीन जारी है।

बिहार : जनता फ्लैट में रुई के गोदाम में भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख, घरों से बाहर भागे लोग

पटना (एजेंसी)

बिहार की राजधानी पटना के अगमकुआं थाना क्षेत्र स्थित जनता फ्लैट के पास मंगलवार सुबह रुई के एक गोदाम में भीषण आग लग गई। सुबह करीब चार बजे लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि गोदाम में रखी रुई और अन्य सामान जलकर राख हो गए। वहां खड़ी एक मोटरसाइकिल भी आग की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गई।

घटना के बाद आसपास के घरों में रहने वाले लोगों के बीच अफरा-तफरी मच गई। हालांकि, दमकल की तीन से चार गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। जानकारी के अनुसार, मंगलवार सुबह करीब चार बजे जनता फ्लैट के पास स्थित रुई के गोदाम में अचानक आग लग गई। आग की लपटें तेजी से फैलने लगीं और कुछ ही देर में पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की तीन से चार गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकलकर्मियों ने स्थानीय लोगों की मदद से काफी मशक्कत की और घंटों बाद आग पर काबू पाया। इस हादसे में गोदाम में रखी रुई समेत अन्य सामान जलकर राख हो गया। हालांकि, कुल कितने रुपये का नुकसान हुआ है, इसका वास्तविक आकलन अभी नहीं हो सका है। रुई कारोबारी राहुल कुमार ने बताया कि रात में उन्हें सूचना मिली थी कि उनकी दुकान से चिंगारी निकल रही है। जानकारी मिलते ही वह मौके पर पहुंचे तो देखा कि गोदाम में आग लगी हुई है। इसके बाद सुबह करीब चार बजे फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों के साथ मिलकर गोदाम में रखा सामान बचाने की काफी कोशिश की गई, लेकिन आग इतनी तेजी से फैल गई कि अधिकांश सामान जलकर राख हो गया।

छठ घाटों पर हंगामा करने के आरोप में 15 लोग गिरफ्तार, न्यायालय में किया गया पेश

सीवान (एजेंसी)



बिहार के सीवान में छठ महापर्व के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। आंदर थाना क्षेत्र के अलग-अलग छठ घाटों पर कथित तौर पर शराब के नशे में हंगामा और हो-हल्ला करने के आरोप में पुलिस ने 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों के खिलाफ जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। जानकारी के अनुसार, छठ महापर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए आंदर थाना पुलिस सतर्क थी। थाना अध्यक्ष सुनील कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम लगातार क्षेत्र के अलग-अलग छठ घाटों का निरीक्षण कर रही थी। पर्व के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था या अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस विशेष निगरानी रख रही थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि क्षेत्र के कुछ छठ घाटों पर कुछ लोग कथित तौर पर शराब के नशे में हंगामा और हो-हल्ला कर रहे हैं। सूचना मिलते ही आंदर थाना पुलिस सक्रिय हो गई और टीम मौके पर पहुंची।

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक-एक कर कुल 15 लोगों को हिरासत में लिया। इसके बाद सभी को गिरफ्तार कर थाने लाया गया। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान अजीत कुमार, मृत्युंजय सहनी, विशाल यादव, उमेश यादव, राजा यादव, नीतीश मणीत, विकास यादव, अंकित कुमार, अभिमन्यु यादव, कुंदन यादव, राजाराम यादव, विवेक यादव, चंदन यादव, रंजीत यादव और मंटू यादव के रूप में हुई है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ जरूरी कागजी और कानूनी प्रक्रिया पूरी की। इसके बाद सभी 15 आरोपियों को न्यायालय में पेश कर दिया गया। आंदर थाना अध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि छठ घाटों पर शराब के नशे में हो-हल्ला और हंगामा करने के मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई पूरी करने के बाद सभी को न्यायालय में पेश किया है। छठ जैसे लोक आस्था के महापर्व के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की इस कार्रवाई की इलाके में चर्चा हो रही है।

बिहार : महिला से रिश्वत मांगने और आपत्तिजनक बातचीत के आरोप में दारोगा निलंबित, जांच रिपोर्ट देने का निर्देश

मोतिहारी (एजेंसी)



बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में जमीन विवाद के एक मामले में महिला से रिश्वत लेने और आपत्तिजनक बातचीत करने के आरोप में सुगौली थाने में तैनात एक दारोगा को निलंबित कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर दारोगा और महिला के बीच बातचीत का ऑडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने यह कार्रवाई की।

निलंबित पुलिस पदाधिकारी की पहचान शैलेश कुमार के रूप में हुई है। मामले की विस्तृत जांच की जिम्मेदारी रक्सौल के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को सौंपी गई है और 24 घंटे के भीतर जांच प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया गया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के अनुसार, सोशल मीडिया पर प्रसारित ऑडियो रिकॉर्डिंग के अवलोकन से सुगौली थाना के एक पुलिस पदाधिकारी द्वारा जमीन विवाद से संबंधित मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं करने और मामले को रफा-दफा करने के एवज में चार हजार रुपये लेने तथा आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने से संबंधित बातचीत सामने आई। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुगौली के पर्यवेक्षी पदाधिकारी पुलिस निरीक्षक मुन्ना कुमार से जांच कराई गई। जांच में पता चला कि सात अक्टूबर को एक महिला ने सुगौली थाने में आवेदन देकर जमीन विवाद के दौरान झोपड़ी में आग लगाने और तोड़फोड़ का आरोप लगाया था। इस मामले की जांच अवर निरीक्षक शैलेश कुमार कर रहे थे। इसी दौरान प्राथमिकी दर्ज नहीं करने और मामले को रफा-दफा करने के एवज में चार हजार रुपये लेने से संबंधित बातचीत हुई थी।

वायरल ऑडियो में महिला दारोगा से शिकायत करती सुनाई देती है कि वह उसके पक्ष में काम नहीं कर रहे हैं। इस पर दारोगा कथित तौर पर कहता है, 'तुम एक रात आओ, हम तुम्हारे तरफ से हो जाएंगे।' महिला बातचीत के दौरान पहले ही दो बार में चार हजार रुपये देने की बात भी कहती है। इसके अलावा, महिला से 20 हजार रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप भी सामने आया है। पुलिस के अनुसार, प्रथमदृष्टया शैलेश कुमार की संलिप्तता प्रतीत होती है। उनके इस आचरण से आम जनमानस में पुलिस के प्रति अविश्वास और असंतोष की भावना उत्पन्न हुई है। साथ ही, यह विभागीय अनुशासन और नियमों के प्रतिकूल है तथा इससे पुलिस की छवि और गरिमा धूमिल हुई है। इन्हीं तथ्यों के आधार पर शैलेश कुमार को संदिग्ध आचरण के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, रक्सौल को पूरे मामले की विस्तृत जांच कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है।

अमेरिका के पूर्व कांग्रेसमैन जिम मैकडरमॉट का निधन, 89 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

वाशिंगटन (एजेंसी)



एक डेमोक्रेट और मनोचिकित्सक के रूप में, उन्होंने 1989 से 2017 तक, 14 कार्यकाल के लिए वाशिंगटन राज्य के सिएटल-आधारित 7वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट का प्रतिनिधित्व किया। उनके बाद भारतीय-अमेरिकी कांग्रेसवुमन प्रमिला जयपाल ने यह जिम्मेदारी संभाली

अमेरिका के पूर्व कांग्रेसमैन जिम मैकडरमॉट का निधन हो गया है। वे 89 साल के थे। मैकडरमॉट को भारत का पुराना दोस्त माना जाता था। वे कांग्रेसनल कॉकस ऑन इंडिया एंड इंडियन अमेरिकंस के संस्थापक सदस्य और पूर्व को-चेयर थे। उन्होंने भारत-अमेरिका को करीब लाने और सिविल न्यूक्लियर डील को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई थी।

मैकडरमॉट का गुरुवार रात सिएटल के हार्बरव्यू मेडिकल सेंटर में निधन हो गया। एक डेमोक्रेट और मनोचिकित्सक के रूप में, उन्होंने 1989 से 2017 तक, 14 कार्यकाल के लिए वाशिंगटन राज्य के सिएटल-आधारित 7वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट का प्रतिनिधित्व किया। उनके बाद भारतीय-अमेरिकी कांग्रेसवुमन प्रमिला जयपाल ने यह जिम्मेदारी संभाली। भारत के साथ उनके जुड़ाव में परमाणु-संबंधी प्रतिबंधों को हटाने के प्रयास, आतंकवादी हमलों के बाद एकजुटता जताना और भारतीय नेताओं का वाशिंगटन में स्वागत करने वाले कानून लाना शामिल था। अप्रैल 2001 में, मैकडरमॉट ने रिपब्लिकन कांग्रेसमैन एड रॉयस के साथ मिलकर एक कानून पेश किया, जिसका उद्देश्य 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद भारत और पाकिस्तान पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाना था। पांच साल बाद, मुंबई ट्रेन बम धमाकों के दिन, उन्होंने हाउस (संसद) में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और भारत के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की थी। 11 जुलाई 2006 को उन्होंने कहा, भारत एक महान राष्ट्र है, और यहां के लोगों की नेक भावना आज के इस दुखद समय से उबरने में मदद करेगी। उन्होंने अपनी बात इन शब्दों के साथ समाप्त कीः भारत, हम आपके साथ खड़े हैं। उन्होंने 2000 से 2002 तक डेमोक्रेटिक सह-अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और 2007 में फिर से नेतृत्व में लौटे।

दिसंबर 2010 में, उनके स्थान पर जो क्राउली को चुना गया। भारत के साथ संबंधों का समर्थन करने के बावजूद, उन्होंने नागरिक परमाणु समझौते का समर्थन नहीं किया। मैकडरमॉट ने जुलाई 2006 में इससे जुड़े कानून के खिलाफ और सितंबर 2008 में परमाणु सहयोग समझौते को मंजूरी देने वाले कानून के खिलाफ वोट दिया। हालांकि, ये दोनों प्रस्ताव पारित हो गए। जुलाई 2006 में 'कांग्रेसनल रिकॉर्ड' में अपना पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा कि भारत को परमाणु हथियारों के लिए 'फिसाइल मटेरियल' (विखंडनीय सामग्री) के उत्पादन को समाप्त करने का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने कहा, जब तक भारत 'फिसाइल मटेरियल' के उत्पादन को खत्म करने का संकल्प नहीं लेता, तब तक मैं इस समझौते को आगे बढ़ाने का समर्थन नहीं कर सकता। इसके बावजूद, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि समझौते का विरोध करने वालों को भारतीय मित्रों के बीच कोई गलत संदेश नहीं भेजना चाहिए, और अन्य क्षेत्रों में सहयोग जारी रह सकता है। जनवरी 2007 में 'इंडिया अब्रॉड' को दिए एक साक्षात्कार में, उन्होंने अपने वोट को भारत के खिलाफ नहीं, बल्कि बुश प्रशासन के विरोध के रूप में बताया। इसके बाद, नवंबर 2009 में मैकडरमॉट ने एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह का अमेरिका में स्वागत किया गया था। इस प्रस्ताव में सुरक्षा, व्यापार, तकनीक, विज्ञान और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में बढ़ते संबंधों के साथ-साथ अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों के योगदान को भी मान्यता दी गई थी।

रिटायरमेंट के बाद भी भारतीय प्रतिनिधियों के साथ उनके संबंध बने रहे। राज्यसभा सदस्य मिलिंद देवड़ा ने एक्स पर उन्हें एक पारिवारिक मित्र और 'भारत का सच्चा दोस्त' बताते हुए याद किया। जयपाल ने बताया कि 11 सितंबर के हमलों के बाद जिन समुदायों को नफरत और विरोध का सामना करना पड़ा, मैकडरमॉट ने उनका समर्थन किया था।

कौन होते हैं 'बैकपैकर्स', जिन्हें ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने दी बड़ी राहत, क्यों बदली वीजा नीति

सिडनी (एजेंसी)



ऑस्ट्रेलिया में इन दिनों 'बैकपैकर्स' प्रवासन नीति चर्चा में है। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज की सरकार ने विदेशी पर्यटकों और अस्थायी कामगारों के लिए 'वर्किंग हॉलिडे वीजा' के नियमों में प्रस्तावित सख्ती को नरम करने का फैसला किया है। सरकार ने मंगलवार को कहा कि 'वर्किंग हॉलिडे वीजा' पर आने वाले पर्यटकों को ग्रामीण इलाकों में अतिरिक्त काम करना होगा।

सरकार ऐसा इसलिए कर रही है ताकि वह प्रवासन में कमी और कृषि, पर्यटन और होटल उद्योगों में कामगारों की कमी के बीच संतुलन बना सके। लेकिन सवाल है कि आखिर ये बैकपैकर्स कौन होते हैं और ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था में इनकी इतनी अहमियत क्यों है? दरअसल, बैकपैकर्स ऐसे युवा विदेशी यात्री होते हैं, जो कम खर्च में किसी दूसरे देश की यात्रा करते हैं। वे आमतौर पर अपने साथ एक बैग लेकर लंबी यात्रा पर निकलते हैं और घूमने के दौरान खर्च चलाने के लिए अलग-अलग जगहों पर अस्थायी काम भी करते हैं। इनका उद्देश्य केवल पर्यटन करना नहीं, बल्कि किसी देश की संस्कृति, रहन-सहन और कामकाज को करीब से समझना भी होता है। ऑस्ट्रेलिया में ऐसे यात्रियों के लिए 'वर्किंग हॉलिडे मेकर' वीजा कार्यक्रम चलाया जाता है। इसके तहत पात्र देशों के युवा सीमित अवधि के लिए ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं, घूम सकते हैं और अपनी यात्रा का खर्च उठाने के लिए काम भी कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से 18 से 30 वर्ष के युवाओं को मौका मिलता है, जबकि कुछ देशों के नागरिकों के लिए आयु सीमा 35 वर्ष तक है। इसमें वीजा की पात्रता और शर्तें संबंधित देश के साथ हुए समझौते पर निर्भर करती हैं।

बलूच लिबरेशन आर्मी का दावा, 'ड्रोन हमले में मारे गए 6 पाकिस्तानी सैनिक'

क्वेटा (एजेंसी)



बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने दावा किया है कि उसकी हवाई और ड्रोन युद्ध इकाई ने पिछले कुछ दिनों में बलूचिस्तान के अलग-अलग हिस्सों में चार सैन्य अभियान चलाए, जिनमें पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के छह जवान मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। सोमवार को जारी एक बयान में, बीएलए प्रवक्ता जीयांद बलोच ने कहा कि समूह की हवाई और ड्रोन युद्ध इकाई, 'कहर' ने पूरे प्रांत में कई अभियानों के जरिए पाकिस्तानी सेना के कैंपों, चौकियों और काफिलों को निशाना बनाया। उन्होंने बताया कि 14 नवंबर को मस्तंग के कुदैंप इलाके में, पाकिस्तानी सेना के काफिले को टारगेट किया गया। यहां से गुजर रहे एक वाहन पर हमला किया गया। यह अभियान समूह की खुफिया शाखा, 'जिराब,' से मिली विश्वसनीय जानकारी के आधार पर चलाया गया था। इस हमले में एक वरिष्ठ अधिकारी समेत पाकिस्तानी सेना के दो जवान मारे गए।

बीएलए के आधिकारिक मीडिया विंग और चैनल 'हकल' ने इस हमले का 1 मिनट 25 सेकंड का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें उनकी ड्रोन इकाई 'कहर' को मस्तंग के कुदैंप इलाके में पाकिस्तानी सेना के काफिले की एक गाड़ी को निशाना बनाते हुए देखा जा सकता है। 'द बलोचिस्तान पोस्ट' की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तानी सेना की 'इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस' ने दो जवानों की मौत की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि एक ड्रोन हमले में सेना के वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य जवानों को निशाना बनाया गया था। बीएलए के बयान के मुताबिक, समूह ने 11 नवंबर को मस्तंग के खादकोचा इलाके में पाकिस्तानी सेना के मुख्य कैंप पर भी ड्रोन हमले किए, जिसमें उनके महत्वपूर्ण ठिकानों और प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इन हमलों में सुरक्षा बल के दो जवान मारे गए और काफी आर्थिक नुकसान हुआ। प्रवक्ता ने आगे बताया कि 9 नवंबर को 'कहर' इकाई ने खादकोचा में पाकिस्तानी सेना के मुख्य कैंप पर ड्रोन हमला किया। उन्होंने कहा कि समूह ने सैन्य कैंप के अंदर मौजूद सैनिकों और बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बनाया, जिसमें सुरक्षा बल का एक जवान मौके पर ही मारा गया।

लादेन का पता बताने वाले डॉक्टर की रिहाई तक, अमेरिका से पाकिस्तान को नहीं मिलेगी 3.3 करोड़ डॉलर की मदद

वाशिंगटन (एजेंसी)



अमेरिका की सीनेट में वित्त वर्ष 2027 के विदेशी सहायता बजट से जुड़े एक विधेयक में पाकिस्तान को दी जाने वाली 3.3 करोड़ डॉलर की सहायता पर एक शर्त रखी गई है। देश ने डॉ. शकील अफरीदी की रिहाई की शर्त बरकरार रखने का प्रस्ताव रखा है।

वहीं, इसी विधेयक के साथ जारी व्याख्यात्मक बयान में अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच निवेश सहयोग बढ़ाने वाले क्वाड इन्वेस्टर्स नेटवर्क के लिए 50 लाख डॉलर देने की सिफारिश की गई है। सीनेट की विनियोग समिति ने सोमवार को वित्त वर्ष 2027 के विदेश विभाग, विदेशी संचालन और संबंधित कार्यक्रमों के लिए बजट विधेयक का मसौदा जारी किया। हालांकि, ये अभी प्रस्ताव हैं।

इन्हें कानून बनने के लिए कांग्रेस की मंजूरी और आगे की विधायी प्रक्रिया से गुजरना होगा। विधेयक की धारा 7044 (बी) के तहत पाकिस्तान के लिए निर्धारित 3.3 करोड़ डॉलर की सहायता तब तक जारी नहीं की जा सकेगी, जब तक अमेरिकी विदेश मंत्री कांग्रेस को यह प्रमाणित नहीं कर देते कि शकील अफरीदी को रिहा कर दिया गया है और ओसामा बिन लादेन का पता लगाने में अमेरिका की मदद करने से जुड़े आरोपों से उन्हें मुक्त कर दिया गया है। यह प्रावधान पाकिस्तान को मिलने वाली पूरी अमेरिकी सहायता पर रोक लगाने का प्रस्ताव नहीं है, बल्कि सहायता की एक निर्धारित राशि पर पहले से लागू प्रतिबंध को बरकरार रखने से संबंधित है। अफरीदी पाकिस्तान के डॉक्टर हैं, जिन्होंने 2011 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए को ओसामा बिन लादेन का पता लगाने में मदद की थी।

मई 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में अमेरिकी सैन्य अभियान में बिन लादेन मारा गया था। इसके बाद अफरीदी को गिरफ्तार कर लिया गया था। उनकी मूल 33 साल की सजा 2014 में घटाकर 23 साल कर दी गई थी। विधेयक के साथ जारी व्याख्यात्मक बयान में क्वाड इन्वेस्टर्स नेटवर्क के लिए 50 लाख डॉलर की सिफारिश भी की गई है। इसका उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र और अमेरिका में उभरती महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना है। इस नेटवर्क में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। यह प्रस्ताव हिंद-प्रशांत रणनीति के समर्थन के लिए निर्धारित कम से कम 1.8 अरब डॉलर की राशि से अलग है।

समिति के बजट सारांश में चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए बनाए गए फंड के तहत 40 करोड़ डॉलर का भी प्रावधान सूचीबद्ध है। भारत और नेपाल में रह रहे तिब्बती शरणार्थियों से जुड़े कार्यक्रमों को भी विधेयक में जगह दी गई है।

सीबीआई ने निशा भगत मौत मामले में क्राइम सीन किया रिक्रिएट, आरोपी अजय तिर्की से घंटों हुई पूछताछ

रांची (एजेंसी)

झारखंड की आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता निशा भगत की मौत के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने जांच तेज कर दी है। एजेंसी ने सोमवार देर शाम पिठोरिया में घटनास्थल का निरीक्षण कर क्राइम सीन रिक्रिएट किया। इसी स्थान पर निशा भगत ने 6 नवंबर को फेसबुक लाइव करते हुए कथित रूप से फांसे लगा ली थी। जांच एजेंसी ने इस मामले में नामजद आरोपी केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की लंबी पूछताछ की। सीबीआई की टीम सोमवार को ही अजय तिर्की के आवास पर पहुंची थी और जांच-पड़ताल के बाद मंगलवार सुबह वहां से निकली। सीबीआई की टीम ने अजय तिर्की के अलावा इस मामले में दूसरी नामजद आरोपी ज्योत्सना केरकेट्टा के ठिकानों पर सोमवार की शाम छापेमारी की थी। करीब आठ घंटे तक चली कार्रवाई के दौरान दस्तावेज और मोबाइल फोन जब्त किए जाने की जानकारी सामने आई है। टीम ने स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की है।

सीबीआई नई दिल्ली स्थित विशेष अपराध-1 शाखा ने 14 नवंबर को निशा भगत के मौत के केस के री-रजिस्टर (आरसी 0482026 एस0007) करते हुए जांच शुरू की है। यह प्राथमिकी रांची के पिठोरिया थाने में 7 नवंबर को दर्ज मूल प्राथमिकी संख्या 114/2026 के आधार पर दर्ज की गई है। सीबीआई ने अजय तिर्की, ज्योत्सना केरकेट्टा और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 और 61(2) के तहत मामला दर्ज किया है। इनमें आत्महत्या के लिए उकसाने और आपराधिक साजिश से जुड़े आरोपों की जांच की जा रही है। निशा भगत ने 6 नवंबर को रांची के पिठोरिया क्षेत्र में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी।

भस्म आरती में दिखा बाबा महाकाल का दिव्य स्वरूप, रवीना टंडन बेटी राशा के साथ पहुंचीं मंदिर

उज्जैन (एजेंसी)



विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में मंगलवार सुबह कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल का विशेष पूजन-अभिषेक और आकर्षक श्रृंगार किया गया। सुबह चार बजे मंदिर के पट खुलने के साथ शुरू हुई भस्म आरती में बाबा महाकाल को पंचामृत से स्नान कराया गया। इसके बाद चांदी का मुकुट और मुंड माला धारण कराकर चंद्रमा, त्रिशूल और त्रिपुंड से विशेष श्रृंगार किया गया। अंत में भगवान को भस्म अर्पित की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दिव्य स्वरूप के दर्शन किए। मंदिर परिसर जय श्री महाकाल के उद्घोष से गूंज उठा।

पंचामृत से अभिषेक के बाद बाबा महाकाल को रमाई गई भस्म

श्री महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी पंडित महेश शर्मा ने बताया कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर बाबा महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया। मंगलवार सुबह चार बजे भस्म आरती के लिए मंदिर के पट खुलते ही पंडे-पुजारियों ने गर्भगृह में स्थापित सभी देवी-देवताओं की प्रतिमाओं का पूजन किया।

इसके बाद भगवान महाकाल का जलाभिषेक किया गया और दूध, दही, घी, शक्कर तथा फलों के रस से तैयार पंचामृत अर्पित किया गया। पूजन के बाद प्रथम घंटाल बजाकर हरि ओम का जल अर्पित किया गया। कपूर आरती के बाद बाबा महाकाल को चांदी का मुकुट और मुंड माला धारण कराई गई। इसके बाद चंद्रमा, त्रिशूल और त्रिपुंड से भगवान का विशेष श्रृंगार किया गया। अंत में बाबा महाकाल को भस्म रमाई गई और उन्होंने भक्तों को दिव्य दर्शन दिए। भस्म आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। भक्तों ने भगवान के मनमोहक स्वरूप के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और भक्ति में लीन होकर जय श्री महाकाल के जयकारे लगाए। मान्यता है कि भस्म अर्पित करने के बाद भगवान निराकार से साकार स्वरूप में भक्तों को दर्शन देते हैं।

अभिनेत्री रवीना टंडन और राशा टंडन ने किए महाकाल के दर्शन

मंगलवार को बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन और उनकी पुत्री अभिनेत्री राशा टंडन भी श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचीं। दोनों ने बाबा महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से सहायक प्रशासन एवं जनसंपर्क अधिकारी आशीष फलवड़िया ने दोनों अभिनेत्रियों का स्वागत और सम्मान किया।

केरल : नौ महीनों में दर्ज हुए दुष्कर्म के 1993 मामले, हर दिन औसतन सात से ज्यादा महिलाएं हो रहीं शिकार

तिरुवनंतपुरम (एजेंसी)

केरल में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर दावे तो बहुत किए जाते हैं लेकिन हकीकत ठीक इसके उलट है। पुलिस के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष के पहले नौ महीनों में दुष्कर्म के 1993 मामले दर्ज हुए हैं। यानी हर दिन औसतन सात से ज्यादा महिलाएं दुष्कर्म का शिकार हो रही हैं। ये आंकड़े इसलिए भी अहम हैं क्योंकि सीएम सतीशन की सरकार बुधवार को अपने कार्यकाल के छह महीने पूरे कर रही है और महिलाओं की सुरक्षा नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बनकर उभरी है। 11 नवंबर को जारी किए गए आंकड़े के मुताबिक, राज्य में 2025 में दुष्कर्म के 2952 केस दर्ज हुए थे जबकि 2024 में 2,901 और 2023 में 2,562 केस दर्ज हुए थे। 2016 में जब पिनाराई विजयन की लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) पहली बार सत्ता में आई थी, तो यह संख्या 1,656 थी। अगले नौ सालों में यह आंकड़ा लगभग 78 प्रतिशत बढ़ा है। अपने दस साल के शासन के दौरान एलडीएफ सरकार और उसके नेताओं ने अक्सर केरल को महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक मॉडल राज्य के तौर पर पेश किया और महिलाओं के खिलाफ अपराधों की आलोचना को राज्य की इमेज खराब करने की कोशिश बताकर जवाब दिया। आंकड़े यह भी दिखाते हैं कि परिवारों के अंदर हिंसा एक बड़ी चिंता बनी हुई है। इस वर्ष सितंबर तक पतियों या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता के 2,558 मामले दर्ज किए गए।

ये आंकड़े 2025 में 3,986, 2024 में 4,515 और 2023 में 4,710 थे। 2016 में दहेज से होने वाली मौतें 25 थीं, जो इस दशक में सबसे ज्यादा थीं। केरल में 2025 में ऐसी छह मौतें और इस साल सितंबर तक एक मौत हुई।

पंजाब में पराली जलाने के 6,433 मामले दर्ज, 2,252 किसानों पर 1.12 करोड़ जुर्माना

पटियाला (एजेंसी)



पंजाब में धान की कटाई के साथ पराली जलाने की घटनाओं को लेकर पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) और प्रशासन की ओर से निगरानी एवं कार्रवाई जारी है। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 16 नवंबर 2026 तक की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में पराली जलाने की कुल 6,433 घटनाएं दर्ज की गई हैं। वहीं, राज्य में धान की कुल 32.87 लाख हेक्टेयर भूमि में से 98.50 प्रतिशत क्षेत्र में कटाई पूरी हो चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार पराली जलाने की घटनाओं को लेकर अब तक 5,721 खेतों का निरीक्षण किया गया है। इनमें से 2,524 स्थानों पर फसल अवशेष जलाने की पुष्टि हुई है। वहीं, 294 ऐसे खेत भी मिले हैं, जहां गैर-एएफएल श्रेणी में पराली जलाने के निशान पाए गए। इन मामलों में कुल 2,252 पर्यावरणीय मुआवजे (ईसी) के मामले लगाए गए हैं। इन पर 1 करोड़ 12 लाख 95 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जबकि 40 लाख 60 हजार रुपये की राशि वसूल की जा चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक, पराली जलाने के मामलों में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 के तहत कुल 1,971 मामले दर्ज किए गए हैं।

इसके अलावा, 2,066 मामलों में राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है। निगरानी अधिकारियों के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की धारा 14 के तहत 35 मामलों में अभियोजन कार्रवाई शुरू की गई है। हालांकि अधिकारियों के खिलाफ कोई चार्जशीट जारी नहीं हुई और न ही किसी अधिकारी को निलंबित किया गया है। राज्य में कुल 1,607 चेतावनी नोटिस और कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। पटियाला जिले में अब तक पराली जलाने की 416 घटनाएं दर्ज की गई हैं। जिले में धान की कुल 2.314 लाख हेक्टेयर भूमि में से 99 प्रतिशत क्षेत्र में कटाई पूरी हो चुकी है। प्रशासन की ओर से 366 खेतों का निरीक्षण किया गया, जिनमें 230 स्थानों पर पराली जलाने की पुष्टि हुई। वहीं, चार गैर-एएफएल खेतों में पराली जलाने के निशान मिले हैं। पटियाला जिले में पर्यावरणीय मुआवजे के 170 मामले लगाए गए हैं और कुल 8 लाख 45 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसमें से 3 लाख 10 हजार रुपये की वसूली हुई है। इसके अलावा 222 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 141 मामलों में राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है।

आंध्र प्रदेश : अकवान के गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना, 3 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान

अमरावती (एजेंसी)



बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात 'अकवान' अभी एक ही जगह पर स्थिर है। इस चक्रवात के मंगलवार शाम तक एक 'गंभीर चक्रवाती तूफान' में बदलने की संभावना है। इसको तूफान को लेकर आंध्र प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सलाह दी है। आंध्र प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एपीएसडीएमए) के प्रबंध निदेशक और आरटीजीएस के सीईओ प्रखर जैन ने बताया कि चक्रवात 'अकवान' पिछले कई घंटों से एक ही जगह पर स्थिर है। इस चक्रवात के मंगलवार शाम तक एक 'गंभीर चक्रवाती तूफान' में बदलने की संभावना है। फिलहाल यह चक्रवात चेन्नई से 610 किमी, मछलीपट्टनम से 660 किमी, विशाखापत्तनम से 670 किमी और ओडिशा के गोपालपुर से 790 किमी दूर स्थित है। आंध्र प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एपीएसडीएमए) के प्रबंध निदेशक और आरटीजीएस के सीईओ प्रखर जैन ने बताया कि चक्रवात 'अकवान' पिछले कई घंटों से एक ही जगह पर स्थिर है।

इस चक्रवात के मंगलवार शाम तक एक 'गंभीर चक्रवाती तूफान' में बदलने की संभावना है। फिलहाल यह चक्रवात चेन्नई से 610 किमी, मछलीपट्टनम से 660 किमी, विशाखापत्तनम से 670 किमी और ओडिशा के गोपालपुर से 790 किमी दूर स्थित है। पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए गुरुवार सुबह तक इसके एक 'बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान' में बदलने की आशंका है।

बिलासपुर में जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

ओपन सर्च. संवाददाता



रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि जनजातीय समाज का गौरवशाली इतिहास साहस, स्वाभिमान, संघर्ष और अपनी संस्कृति एवं परंपराओं की रक्षा का इतिहास है। देश की स्वतंत्रता और समाज के अधिकारों के लिए जनजातीय नायकों ने जो त्याग और बलिदान दिया है, वह हमारी अमूल्य धरोहर है। हमें अपने महान जननायकों के आदर्शों से प्रेरणा लेकर शिक्षा, आत्मनिर्भरता और विकास के माध्यम से समाज को आगे बढ़ाना है तथा विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करनी है। मुख्यमंत्री बिलासपुर के लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने रिमोट का बटन दबाकर लगभग 120 करोड़ रुपए की लागत के 16 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। मुख्यमंत्री ने सभी को जनजातीय गौरव दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा सहित देश के महान जनजातीय नायकों को नमन किया।

उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने अल्पायु में ही अंग्रेजी शासन की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध संघर्ष का बिगुल फूंका और जनजातीय समाज को अपनी संस्कृति, परंपराओं तथा अधिकारों की रक्षा के लिए संगठित किया। उन्होंने तीर-कमान के बल पर अंग्रेजी सत्ता को चुनौती देकर साहस और स्वाभिमान का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत कर जनजातीय समाज के ऐतिहासिक योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिलाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की स्वतंत्रता के लिए जनजातीय समाज ने 1857 की क्रांति से पहले ही संघर्ष शुरू कर दिया था। छत्तीसगढ़ के अमर शहीद वीर नारायण सिंह ने अकाल के समय भूख से व्याकुल लोगों की सहायता की और अन्याय एवं शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई। ऐसे महान जननायकों का संघर्ष और बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणास्रोत रहेगा।

'चार तेज गेंदबाज और एक स्पिनर', वेलिंगटन टेस्ट में भारत की प्लेइंग इलेवन पर कप्तान गिल का संकेत

वेलिंगटन (एजेंसी)



भारत और न्यूजीलैंड के बीच गुरुवार से 2 टेस्ट मैचों की सीरीज वेलिंगटन में शुरू हो रही है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने संकेत दिया है कि टीम इंडिया 4 तेज गेंदबाजों के साथ उतर सकती है। वेलिंगटन टेस्ट से पहले शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चार तेज गेंदबाजों के साथ उतरने के संकेत दिए। हालांकि, उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि चार पूर्ण तेज गेंदबाज होंगे या तीन तेज गेंदबाजों के साथ एक तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर को प्लेइंग इलेवन में जगह दी जाएगी।

गिल ने कहा, हमने यहां जो टेस्ट मैच देखे हैं, उनमें पहले दो दिन अलग मैच होते हैं और अगले तीन दिन थोड़े अलग मैच होते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, हम एक ऐसा पेस अटैक चाहते हैं जो स्विंग और सीम मूवमेंट के साथ ही पिच के फ्लैट होने की स्थिति में भी प्रभावी हो। उन्होंने कहा, हम निश्चित रूप से चार तेज गेंदबाजी विकल्प चाहते हैं, लेकिन हम अभी भी तय कर रहे हैं कि वे तेज गेंदबाज कौन से हैं। हमने कई बार तीसरे, चौथे और पांचवें दिन देखा है कि विकेट, खासकर पुरानी गेंद से, थोड़ा फ्लैट हो जाता है, इसलिए हमारी फास्ट-बॉलिंग यूनिट से, हम ऐसा चाहते हैं जिसके पास पेस हो, कोई ऐसा जो लगातार सही एरिया में हिट कर सके, और फिर जाहिर है कि एक छोर से कंट्रोल करने के लिए एक स्पिनर के साथ जाना चाहिए, क्योंकि अगर हवा तेज हो तो हवा के खिलाफ गेंदबाजी करना आसान नहीं होगा।

तेज गेंदबाज की भूमिका लगभग आधी हो जाती है, अगर वो हवा के खिलाफ गेंदबाजी कर रहा हो, इसलिए बहुत सारे फैक्टर हैं जिन पर हम ध्यान देंगे। भारत की प्लेइंग इलेवन में रवींद्र जडेजा अकेले स्पिनर हो सकते हैं, जो नंबर 7 पर बल्लेबाजी करेंगे। टीम में बल्लेबाजी ऑर्डर पर गिल ने कहा, हम सात बल्लेबाज देख रहे हैं और फिर आठ और नौ इस पर निर्भर करेंगे। आकाश और अंशुल थोड़ी बल्लेबाजी कर सकते हैं।

अगर हम रेड्डी के साथ भी जाते हैं, तो वह एक पूर्ण बल्लेबाज है, इसलिए हम देखेंगे कि हम किस तरह के कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहते हैं और हम असल में क्या करना चाहते हैं। भारतीय टीम के पास तेज गेंदबाजी विकल्प के रूप में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप, अंशुल कंबोज और गुरनूर बरार हैं।

न्यूजीलैंड को लगा तगड़ा झटका, मिशेल सेंटनर भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हुए

भारत के खिलाफ 19 नवंबर से शुरू हो रही 2 टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले न्यूजीलैंड को तगड़ा झटका लगा है। अनुभवी ऑलराउंडर मिशेल सेंटनर दाहिने हाथ में फ्रैक्चर की वजह से टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। सेंटनर को यह चोट रविवार माउंट माउंगानुई में भारत के खिलाफ पांचवें वनडे में अर्शदीप सिंह के फेंके बाउंसर से लगी। न्यूजीलैंड क्रिकेट की एक रिलीज के मुताबिक, 'स्कैन से पता चला है कि सेंटनर के दाहिने हाथ में फ्रैक्चर है।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उनके शामिल होने की जानकारी सही समय पर दी जाएगी।' टेस्ट सीरीज के लिए मिशेल सेंटनर की जगह न्यूजीलैंड टीम में स्पिन-बॉलिंग ऑलराउंडर डीन फॉक्सक्रॉफ्ट को शामिल किया गया है। 28 साल के फॉक्सक्रॉफ्ट ने मई में बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ एक टेस्ट खेला था। उन्होंने उस मैच में 98 रन बनाए थे। सेंटनर की गैरमौजूदगी में एक स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर के रूप में ग्लेन फिलिप्स की भूमिका अहम होगी। चोट सेंटनर



की टेस्ट उम्मीदों के लिए एक झटका है, क्योंकि उन्होंने बिग बैश लीग में एडिलेड स्ट्राइकर्स के एक आकर्षक ऑफर को ठुकरा दिया था ताकि वे सभी फॉर्मेट में अपने न्यूजीलैंड करियर पर ध्यान दे सकें। सेंटनर ने उस समय न्यूजीलैंड हेराल्ड से कहा था, जब आप आगे की गर्मियों को देखते हैं, भारत यहां सफेद गेंद और टेस्ट के लिए है और ऑस्ट्रेलिया से भी सीरीज होनी है। इससे बड़ा और रोमांचक कुछ नहीं है। मैं अभी भी इसका हिस्सा बनना चाहूंगा। न्यूजीलैंड को ऑस्ट्रेलिया में 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है। यह सीरीज 9 दिसंबर से शुरू होगी।

पीसीबी ने शेन डिट्ज को पाकिस्तान महिला टीम का हेड कोच बनाया

नई दिल्ली (एजेंसी) पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर शेन डिट्ज को पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम के हेड कोच के रूप में नियुक्त किया है। शेन डिट्ज वेस्टइंडीज के खिलाफ द्विपक्षीय सीरीज से कार्यभार संभालेंगे। पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम का हेड कोच नियुक्त किए जाने के बाद शेन डिट्ज ने कहा, 'पाकिस्तान महिला टीम का हेड कोच बनकर मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं। पाकिस्तान क्रिकेट का इतिहास बहुत शानदार रहा है और मुझे याद है कि जब मैं एक युवा खिलाड़ी था, तो 1992 में ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप फाइनल में उन्हें चीयर करता था, जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी।'



पीसीबी की तरफ से जारी एक बयान में उन्होंने कहा, 2028 में हम टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेंगे। हमारा मकसद समर्थकों को घरेलू मैदान पर चीयर करने का मौका देना है। वर्ल्ड कप में कॉम्पिटिटिव बने रहने के लिए हमें बहुत काम करना है और हम सभी को खिलाड़ियों और स्टाफ के तौर पर वर्ल्ड-क्लास परफॉर्मेंस देने के लिए विकसित होना होगा। उन्होंने कहा, मैं पहले तीन बार पाकिस्तान का दौरा कर चुका हूं। यहां क्रिकेट के लिए प्यार और जुनून लोगों को अपनी ओर खींचता है। मैं टीम के साथ काम करने के लिए वहां जाने का इंतजार नहीं कर सकता। 51 साल के शेन डिट्ज के पास कोचिंग का लंबा अनुभव है। वह हाल में वेस्टइंडीज महिला टीम के हेड कोच के तौर पर काम कर रहे थे। उनकी कोचिंग में वेस्टइंडीज 2024 और 2026 टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंची थी। इसके पहले डिट्ज बांग्लादेश और नीदरलैंड्स की महिला नेशनल टीमों के साथ काम कर चुके हैं। 2008 से 2013 तक न्यूजीलैंड में क्रिकेट वेलिंगटन के साथ हाई-परफॉर्मेंस कोच के तौर पर भी वह काम कर चुके हैं। पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम से आईसीसी और एसीसी टूर्नामेंटों में बेहतर प्रदर्शन करवाना शेन डिट्ज के लिए एक बड़ी चुनौती होने वाली है।

मेदवेदेव ने एटीपी फाइनल्स के पहले मैच में कोबोली को हराया

ट्यूरिन (एजेंसी) डेनियल मेदवेदेव ने इनाल्पी एरिना में स्थानीय खिलाड़ी ओर डेब्यू कर रहे फ्लेवियो कोबोली को 7-6(4), 6-3 से हराकर अपने एटीपी फाइनल्स कैंपेन की शुरुआत की। मेदवेदेव अपने दूसरे एटीपी फाइनल्स टाइटल की तलाश में हैं। मेदवेदेव ने 2019 से 2024 तक लगातार छह बार एटीपी फाइनल्स में जगह बनाई, जिसमें 2020 का उनका यादगार टाइटल शामिल है। उस मौके पर, उन्होंने ट्रॉफी जीतने के रास्ते में वर्ल्ड नंबर 1 नोवाक जोकोविच, वर्ल्ड नंबर 2 राफेल नडाल और वर्ल्ड नंबर 3 डोमिनिक थिएम को हराया था। 2025 में क्वालिफिकेशन से चूकने के बाद मेदवेदेव ने 2026 सीजन में शानदार वापसी की, चार टूर-लेवल टाइटल जीते और 53 जीत दर्ज कीं। एटीपी टूर पर वर्ल्ड नंबर 1 अलेक्जेंडर ज्वेरेव (66) के बाद यह जीत की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। चौथी वरीयता प्राप्त मेदवेदेव का अगला मुकाबला बुधवार को कार्लोस अल्काराज से होगा। इवान लेंडल ग्रुप में 0-1 से पिछड़ने के बाद, कोबोली अब बेरेटिनी, जानिक सिनर और लोरेंजो मुसेट्टी के साथ इस इवेंट में सिंगल्स में जीत दर्ज करने वाले चौथे इटैलियन पुरुष बनने की अपनी कोशिश जारी रखना चाहेंगे। उनका अगला मुकाबला फ्रांसेस टियाफो से होगा। इससे पहले, दूसरी वरीयता प्राप्त कार्लोस अल्काराज ने फ्रांसेस टियाफो को 6-2, 6-2 से हराकर इवान लेंडल ग्रुप में 1-0 की बढ़त बना ली थी। अल्काराज साल के आखिर में होने वाले इस इवेंट में चौथी बार हिस्सा ले रहे हैं। उनका सबसे अच्छा नतीजा पिछले साल आया था, जब वह टाइटल मैच में जानिक सिनर से हार गए थे। स्पेन के 23 वर्षीय खिलाड़ी जबरदस्त फॉर्म में उत्तरी इटली पहुंचे हैं और उन्होंने पिछले महीने पेरिस और वियना में लगातार टाइटल जीते हैं। अल्काराज इस सप्ताह अपने 30वें टूर-लेवल टाइटल और सीजन के छठे टाइटल की तलाश में हैं। कलाई की चोट के कारण वह साल के चार महीने बाहर रहे। अगस्त में यूएस ओपन में वापसी के बाद से उन्होंने अपने 22 में से 20 मैच जीते हैं।



धोनी ने आईपीएल से लिया संन्यास, चेन्नई सुपरकिंग्स के मेंटर बने



चेन्नई (एजेंसी)

चेन्नई सुपर किंग्स के दिग्गज खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी ने इंडियन प्रीमियर लीग से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही वह लीग के 2027 सत्र से फ्रेंचाइजी के साथ एक नई भूमिका में नजर आएंगे और टीम के मेंटर की जिम्मेदारी संभालेंगे।

45 वर्षीय विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) से संन्यास ले लिया है। धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) को रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए पांच आईपीएल खिताब जिताए और 200 से अधिक मैचों में टीम की कप्तानी की। पूर्व भारतीय कप्तान आईपीएल इतिहास के पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने किसी एक टीम की 212 मैचों में कप्तानी की। उनकी कप्तानी में सीएसके ने 128 मैच जीते। उनके नेतृत्व में चेन्नई ने 2010, 2011, 2018, 2021 और 2023 में आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम की। सीएसके ने 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए कहा, अनगिनत जीतों, कठिन दौर और हमेशा याद रहने वाली यादों के बीच एमएस शुरू से ही हमारी यात्रा के केंद्र में रहे हैं। टीम को गौरव तक पहुंचाने से लेकर सुपर किंग्स की अगली पीढ़ी का मार्गदर्शन करने तक, धोनी हमेशा हमारी पहचान का हिस्सा रहेंगे और चेन्नई हमेशा उनका घर रहेगा। धोनी अपने पूरे आईपीएल करियर में सीएसके के कप्तान रहे। केवल 2022 में कुछ मैचों के लिए रवींद्र जडेजा ने कप्तानी संभाली थी। हालांकि, टीम के खराब प्रदर्शन के बाद उसी सीजन में धोनी ने फिर से कमान संभाल ली। इसके बाद 2024 में उन्होंने कप्तानी की जिम्मेदारी ऋतुराज गायकवाड़ को सौंप दी।

आईपीएल 2027 : हर्षल पटेल ट्रेड के जरिए सनराइजर्स हैदराबाद से गुजरात टाइटंस पहुंचे

नई दिल्ली (एजेंसी)



हर्षल पटेल आईपीएल 2027 में गुजरात टाइटंस के लिए खेलते नजर आएंगे। हर्षल को सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) ने गुजरात टाइटंस के साथ ट्रेड किया है। पटेल के ट्रेड की आधिकारिक घोषणा मंगलवार को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की गवर्निंग बॉडी ने की। आईपीएल में दो बार पर्पल कैप जीत चुके हर्षल के जुड़ने से गुजरात टाइटंस (जीटी) की गेंदबाजी मजबूत हुई है।

हर्षल पटेल को आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में एसआरएच ने 8 करोड़ रुपये में खरीदा था। पटेल 4 करोड़ रुपये के नुकसान के साथ 4 करोड़ रुपये में गुजरात टाइटंस से जुड़े हैं। इस मूव से पटेल अपने गृह राज्य में भी लौटेंगे। अहमदाबाद में जन्मे इस पेसर ने 2025-26 सीजन से घरेलू क्रिकेट में गुजरात का प्रतिनिधित्व करने के लिए वापसी की। पटेल को आईपीएल का लंबा अनुभव है। उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर अपनी पहचान बनाई है। उन्हें डेथ ओवरों का विशेषज्ञ माना जाता है। पटेल ने 2012 में आईपीएल में डेब्यू के बाद से 124 मैचों में 151 विकेट लिए हैं। उन्होंने दो बार पर्पल कैप जीती है, 2021 और 2024 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) और पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) का प्रतिनिधित्व करते हुए टूर्नामेंट के लीडिंग विकेट-टेकर रहे। हर्षल ने आईपीएल 2025 में 13 मैचों में 16 विकेट लिए थे। पिछला सीजन उनके लिए अच्छा नहीं रहा था। वह सिर्फ 5 मैच खेल पाए थे, जिसमें उन्हें एक भी विकेट नहीं मिला था।

जीटी में तेज गेंदबाज के रूप में कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, जेसन होल्डर और अशोक शर्मा जैसे खिलाड़ी पहले से मौजूद हैं। ऐसे में हर्षल इस गेंदबाजी आक्रमण को और धारदार बनाएंगे।

आईपीएल में पटेल आरसीबी, एसआरएच, पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) के लिए खेल चुके हैं। पटेल भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से भी 25 टी20 मैचों में 29 विकेट ले चुके हैं। एसआरएच ने पहले ही दिल्ली कैपिटल्स से टी नटराजन को लाकर अपनी गेंदबाजी को मजबूत किया था। नटराजन को डीसी में पिछले 2 मैचों में न के बराबर मौके मिले। एसआरएच ने चेन्नई सुपर किंग्स से तेज गेंदबाज खलील अहमद और नाथन एलिस को भी टीम में शामिल किया है।

'सैंडपेपरगेट विवाद पर ऑस्ट्रेलियाई टीम पहले की तरह अब भी विभाजीत': आर अश्विन

नई दिल्ली (एजेंसी)



ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा की लिखी किताब 'सब्र' की रिलीज के बाद से 2018 में केपटाउन टेस्ट के दौरान हुआ सैंडपेपरगेट कांड फिर से चर्चा में है। इस विषय पर ऑस्ट्रेलियाई पूर्व और मौजूदा खिलाड़ियों के बीच एकमत नहीं है। पूर्व भारतीय स्पिनर आर अश्विन ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है। अश्विन ने 2018 में दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर गई ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के सदस्यों के अलग-अलग बयानों पर भी अपनी राय दी।

पूर्व भारतीय स्पिनर ने स्टार स्पोर्ट्स के 'सैंडपेपरगेटः द अनसेटल्ड डिबेट' पर कहा, इस किताब में उस्मान ख्वाजा ने अपनी कहानी स्पष्ट तरीके से बताई है। वह सामूहिक जवाबदेही मांग रहे हैं। वह कह रहे हैं कि केवल तीन लोग ही इसके बारे में जानते थे, और भी लोग थे। उन्होंने कहा, ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस की मैं एक क्रिकेटर के तौर पर सच में तारीफ करता हूं। उन्होंने उस्मान ख्वाजा के दावों को बेबुनियाद, बकवास और बिना सबूत वाला कहा है। वहीं, डेविड वॉर्नर का बयान ख्वाजा का समर्थन करता है। यह चिंता की बात है, चाहे हम इसे कैसे भी देखें। पूर्व स्पिनर ने कहा कि मुझे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ द्वारा केस को दोबारा नहीं खोलने वाला बयान पसंद आया। मुझे लगता है कि यह सही तरीका है। लेकिन अलग-अलग बयानों ने ऑस्ट्रेलियाई ड्रेसिंग रूम में दरारें दिखा दी हैं।

इसमें एक बात बिल्कुल साफ है कि इस पर विचारों और राय को लेकर पहले भी ऑस्ट्रेलियाई ड्रेसिंग रूम में दरारें थीं। मुझे नहीं लगता कि अब भी यह दरार खत्म हुई है। यह मेरे लिए ज्यादा चिंता की बात होगी। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ओपनर ख्वाजा ने अपनी ऑटोबायोग्राफी 'सब्र' में दावा किया है कि पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को पता था कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2018 के टेस्ट मैच के दौरान क्रिकेट बॉल पर सैंडपेपर का इस्तेमाल किया जा रहा था और ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पोर्ट एलिजाबेथ में पिछले टेस्ट में भी ऐसा ही किया था। इस मामले में उस समय के कप्तान स्टीव स्मिथ, ऑन-स्क्रीन सैंडपेपर इस्तेमाल करने वाले कैमरन बैनक्रॉफ्ट और डेविड वॉर्नर को दोषी ठहराया गया था और उन्हें सजा दी गई थी। मौजूदा कप्तान पैट कमिंस और तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क भी उस मैच का हिस्सा थे। ऐसे में कमिंस द्वारा मामले की जानकारी न होना और ख्वाजा के दावों को पूरी तरह से बकवास करार देना विवाद पर मतभिन्नता को दर्शाता है।

आईपीएल 2027 में नहीं खेल पाएंगे ट्रेविस हेड, एसआरएच को फैसले की जानकारी दी

नई दिल्ली (एजेंसी)



इंडियन प्रीमियर लीग 2027 (आईपीएल 2027) से पहले सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) को एक बड़ा झटका लगा है। टीम के लिए खेलने वाले ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत आईपीएल का अगला सीजन नहीं खेलने का फैसला किया है। हेड ने अपने फैसले की जानकारी एसआरएच मैनेजमेंट को दी है। क्रिकइन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक, हेड ने एसआरएच को आईपीएल के अगले सीजन में नहीं खेलने के अपने फैसले के बारे में बताया है।

अगले कुछ महीनों में ऑस्ट्रेलिया का इंटरनेशनल शेड्यूल बहुत व्यस्त रहेगा। ट्रेविस हेड इसी वजह से आईपीएल का अगला सीजन नहीं खेल पाएंगे। अगस्त की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया के हेड कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने क्रिकइन्फो को बताया था कि ऑस्ट्रेलिया को कुछ फैसले लेने होंगे, क्योंकि उनके लिए बहुत सारी जरूरी प्राथमिकताएं सामने हैं। ऑस्ट्रेलियाई टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में खेलने का मौका चाहेगी, जो आईपीएल खत्म होने के ठीक बाद है। एशेज जून से अगस्त तक होगी, उसके बाद अक्टूबर-नवंबर में वनडे वर्ल्ड कप 2027 होगा।

हेड तीन सीजन से एसआरएच के साथ हैं। उन्हें 2024 की नीलामी में फ्रेंचाइजी ने 6.8 करोड़ रुपये में खरीदा था। उन्होंने 2024 सीजन में एसआरएच को फाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई, जहां वे कोलकाता नाइट राइडर्स से हार गए थे। इसके बाद हेड को 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले एसआरएच ने 14 करोड़ में रिटेन किया था। वह रिटेन किए गए पांच खिलाड़ियों में से एक थे।

हेड को आईपीएल से रिलीज करने की मंजूरी मिलने के बाद एसआरएच को यह रकम मिल जाएगी। हेड ने आईपीएल 2024 में 567 रन, आईपीएल 2025 में 374 रन और आईपीएल 2026 में 410 रन बनाए। अभिषेक शर्मा के साथ ट्रेविस हेड की ओपनिंग जोड़ी को लीग की सबसे खतरनाक जोड़ियों में से एक माना जाता है। अगला सीजन न खेलने के हेड के फैसले के बाद एसआरएच को अभिषेक शर्मा के साथ पारी की शुरुआत करने के लिए एक ओपनिंग बल्लेबाज ढूंढना होगा।

बीबीएल 16 : लाबुशेन ब्रिस्बेन हीट के साथ लगातार 11वां सीजन खेलेंगे

ब्रिस्बेन (एजेंसी)



बिग बैश लीग के 16वें सीजन के लिए ब्रिस्बेन हीट ने मार्नस लाबुशेन को रिटेन किया है। लाबुशेन लगातार 11वां सीजन ब्रिस्बेन हीट के लिए खेलेंगे। री-साइन किए गए खिलाड़ियों में लाबुशेन को क्रिस लिन के साथ रखा गया है। क्वींसलैंड क्रिकेट के जनरल मैनेजर–हाई परफॉर्मेंस बेनेट किंग ने कहा कि लाबुशेन का अनुभव और कॉम्पिटिटिव अप्रोच हीट के लिए टूर्नामेंट की तैयारी में बहुत काम आएगा। किंग ने कहा, मार्नस जब भी हीट के लिए खेलते हैं तो अपना शत-प्रतिशत देते हैं। ऐसा बहुत कम है, जो उन्होंने अपने करियर में अब तक क्रिकेट के मैदान पर अनुभव न किया हो। उनकी विविध स्किल्स हमें विरोधी लाइन-अप के खिलाफ मैच-अप और हमारे ओवरऑल स्क्वॉड में संतुलन देंगी। हीट ने युवा तेज गेंदबाज टॉम बाल्किन और ओली पैटरसन को शामिल करके अपनी 18-सदस्यीय टीम में बची हुई जगहें भी भर ली हैं। दोनों खिलाड़ियों ने पिछले सीजन में अच्छा प्रदर्शन किया था। 22 साल के बाल्किन ने पिछले सीजन के पांच मैचों में छह विकेट लिए थे। पैटरसन, जो 20 साल के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, ने पिछले सीजन में तीन मैचों में चार विकेट लिए थे। पैटरसन ने घरेलू सर्किट में भी शानदार प्रदर्शन किया है और लगातार दूसरे सीजन में टी20 मैक्स टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। दोनों युवा खिलाड़ियों ने क्वींसलैंड के लिए डोमेस्टिक वनडे कप में अपना लिस्ट ए डेब्यू किया है, जबकि बाल्किन ने शेफील्ड शील्ड मैच में भी हिस्सा लिया है। किंग ने कहा, मार्नस जैसे बहुत अनुभवी खिलाड़ी और टॉम और ओली जैसे दो युवा तेज गेंदबाज, जिन्होंने बीबीएल में पहले ही दिखा दिया है कि वे क्या कर सकते हैं, के साथ अपनी स्क्वॉड को पूरा कर पाना हमें अगले महीने होने वाले कॉम्पिटिशन में एक मजबूत स्थिति में रखता है। ब्रिस्बेन पिछले एडिशन में पांचवें स्थान पर रहा था और रेगुलर सीजन के आखिरी मैच तक फाइनल में जगह बनाने की दौड़ में बना रहा। अगले महीने जब नया कैप्टन शुरू होगा तो वे उस फिनिश को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। हीट को 12 दिसंबर से 17 जनवरी के बीच गाबा में पांच घरेलू मैच खेलने हैं। उनका कैप्टन मंगलवार, 15 दिसंबर को सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ शुरू होगा।

पहले बल्ले' से 'आखिरी टेस्ट' तक का सफर, एमसीए में सजी सचिन तेंदुलकर की 'बैटोग्राफी'

नई दिल्ली (एजेंसी)



'बैटोग्राफी' पेश की है। यह एमसीए शरद पवार क्रिकेट संग्रहालय का एक अनोखा हिस्सा है, जो भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को समर्पित है। इसमें 25 ऐसे बल्ले शामिल हैं जो 1978 से 2013 तक के उनके शानदार क्रिकेट सफर को दर्शाते हैं। इसके साथ ही, उनके निजी संग्रह से कुछ खास हेडगियर और कपड़े भी रखे गए हैं। 16 नवंबर 2026 को एक विशेष कार्यक्रम में सचिन तेंदुलकर और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अजिंक्य नाइक ने मिलकर 'बैटोग्राफी' का अनावरण किया। यह दिन उस घटना के 13 साल पूरे होने का प्रतीक है, जब 16 नवंबर 2013 को वानखेड़े स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ सचिन तेंदुलकर का 200वां और आखिरी टेस्ट मैच खत्म हुआ था। इसी मैदान पर 27 नवंबर 1983 को 10 साल के तेंदुलकर ने पहली बार कोई टेस्ट मैच देखा था और अपने हीरो विवियन रिचर्ड्स को शतक लगाते हुए देखा था। 'बैटोग्राफी' को इस सोच के साथ तैयार किया गया है कि एक क्रिकेटर की कहानी उसके खेल के सबसे अहम उपकरण (बल्ले) के जरिए बताई जाए। इसमें हर बल्ले को तेंदुलकर के जीवन और करियर के एक अध्याय के रूप में पेश किया गया है। इस संग्रह की शुरुआत उस 'कश्मीर विलो' बल्ले से होती है, जो 1978 में उनकी बड़ी बहन सविता ने उन्हें तब गिफ्ट किया था, जब वे 5 साल के थे और इसका समापन उस बल्ले के साथ होता है, जिसका इस्तेमाल उन्होंने वानखेड़े में अपनी आखिरी टेस्ट पारी में किया था।

जब प्रियंका चोपड़ा ने अभिषेक बच्चन के फोन से एक अभिनेत्री को मैसेज किया



अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने 'सिमी गरेवाल के साथ मुलाकात' शो में अपने सह-कलाकार अभिषेक बच्चन के साथ की गई एक मजेदार शरारत को याद किया। प्रियंका ने बताया कि एक बार उन्होंने अभिषेक का फोन छुपा दिया था और उससे अभिनेत्री रानी मुखर्जी को मैसेज किया था। गौरतलब है कि अभिषेक और रानी के अपने-अपने जीवनसाथी से शादी करने से पहले उनके बीच प्रेम संबंध होने की खबरें थीं। होस्ट सिमी गरेवाल ने प्रियंका से पूछा, क्या आपने कभी उनका मोबाइल चुराया था? प्रियंका ने बताया कि सबसे पहले अभिषेक ने ही उनका फोन चुराकर इस सब की शुरुआत की थी। प्रियंका ने आगे कहा कि उन्होंने इसे अभिषेक पर शरारत करने का मौका समझा। मैंने उसका फोन चुरा लिया और उसे छिपा दिया। मैंने उसके फोन से किसी को मैसेज भेजा... बस इतना कि 'मुझे तुम्हारी याद आ रही है, तुम कहां थीं? क्या तुम...' सिमी ने खुलासा किया कि प्रियंका ने अभिषेक के फोन से रानी को मैसेज किया था, जिसका जवाब रानी ने देते हुए लिखा, हाय एबी, क्या हुआ है तुम्हें? जब प्रियंका ने सिमी से पूछा कि उसे इस घटना के बारे में किसने बताया, तो सिमी ने जवाब दिया, खैर, मैं बहुतों को जानती हूं। हालांकि, प्रियंका को पहले से ही पता था और उसने कहा, मुझे यकीन है कि यह एबी ही है। इस बीच, प्रियंका और अभिषेक का पेशेवर रिश्ता काफी लंबा है। उनका पहला साथ में प्रोजेक्ट 2005 में था, जब उन्होंने रोहन सिप्पी द्वारा निर्देशित फिल्म 'ब्लफमास्टर!' में स्क्रीन शेयर की थी। इस ड्रामा में अभिषेक ने एक ठग का किरदार निभाया था, जबकि प्रियंका उनकी प्रेमिका सिम्मी के रूप में नजर आई थीं। 2008 में, प्रियंका और अभिषेक ने एक बार फिर 'द्रोणा' के लिए साथ काम किया। गोल्डी बहल द्वारा निर्देशित इस फैंटेसी एडवेंचर फिल्म में अभिषेक मुख्य भूमिका में थे, जबकि प्रियंका उनकी रक्षक सोनिया के रूप में दिखाई दी थीं। उनकी आखिरी ऑन-स्क्रीन जोड़ी 2008 में तरुण मनसुखानी की फिल्म 'दोस्ताना' में जॉन अब्राहम के साथ दिखाई दी थी। **(एजेंसी)**

'इंडियन आइडल' के मंच पर भावुक हुईं उर्मिला मतोंडकर, हिंदी सिनेमा और संगीत की सराहना की

अभिनेत्री उर्मिला मतोंडकर हाल ही में सिंगिंग रियलिटी शो 'इंडियन आइडल लेजेंड्स रिटर्न' में गेस्ट के तौर पर शिरकत की। शो में उन्होंने संगीत की विरासत और इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री को आकार देने वाले कलाकारों की सराहना की। शो में उर्मिला ने हिंदी सिनेमा से अपने पर्सनल कनेक्शन के बारे में बात की और बताया कि कैसे म्यूजिक पर्दे पर इमोशन्स और कहानियों को जिंदा करने में अहम भूमिका निभाता है। उर्मिला ने कहा, इंडियन आइडल लेजेंड्स रिटर्न का हिस्सा बनना मेरे लिए काफी पर्सनल रहा है। हिंदी सिनेमा के जादू को करीब से देखने के बाद मैं जानती हूं कि म्यूजिक किसी फिल्म को कितनी गहराई से बदल सकता है, किसी पल को खास बना सकता है और कहानी खत्म होने के बाद भी लोगों के दिलों में बस सकता है। अभिनेत्री ने गानों की महत्ता पर बात करते हुए कहा, कई बार कोई विजुल्स वो बात नहीं कह पाते हैं, जो आवाज कह जाती है। जैसे, किसी सीन में दुख, प्यार या खुशी दिखाया जा रहा हो लेकिन जब उस पर एक अच्छा गाना बजता है, तो वो फीलिंग सीधे दिल तक पहुंच जाती है। इसीलिए म्यूजिक हमारी फिल्मों का इतना जरूरी



हिस्सा है और जब हम उन पुराने गायकों को फिर से स्टेज पर लौटते देखते हैं, तो अपनी पुरानी यादें ताजा करते हैं। उन्होंने कहा, पुराने गायकों की आवाजें दर्शकों की यादों का हिस्सा रही हैं और उन्हें फिर से एक साथ देखना ऐसा लगा जैसे टैलेंट, म्यूजिक और इंडियन आइडल फैमिली का एक खूबसूरत रीयूनियन देख रही हूं। सिंगिंग रियलिटी शो 'इंडियन आइडल लेजेंड्स रिटर्न' शनिवार और रविवार को रात 8:00 बजे प्रसारित होता है। इसमें जाने-माने गायक और संगीतकार हिमेश रेशमिया मुख्य जज के रूप में नजर आ रहे हैं और शो को आदित्य नारायण होस्ट कर रहे हैं। इसमें हिमेश रेशमिया के साथ इंडियन आइडल के 24 पुराने और जाने-माने कंटेस्टेंट्स (महारथी सिंगर्स) ने हिस्सा लिया। इनमें अभिजीत सावंत, अमित सना, सलमान अली, सायली कांबले, ऋषि सिंह, पवनदीप राजन और सलमान अली जैसे लोकप्रिय चेहरे शामिल हैं। इन कंटेस्टेंट्स ने आपस में जोड़ियां बनाकर डिएट्स प्रस्तुत किए, जिनका मूल्यांकन आपसी (पीयर स्कोर) और एक गुप्त जज के स्कोर के आधार पर हुआ। **(एजेंसी)**



अनन्या पांडे की 'कॉल मी बे' सीजन 2 की डेट आई सामने, बेला के किरदार में फिर दिखेंगी अभिनेत्री

मशहूर निर्देशक करण जौहर आगामी वेब सीरीज 'कॉल मी बे' के दूसरे सीजन की वापसी के लिए तैयार हैं। मंगलवार को मेकर्स ने सोशल मीडिया पर सीरीज की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है। मेकर्स ने अपने इंस्टाग्राम पर सीरीज की मुख्य अभिनेत्री अनन्या पांडे का वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह बेला (बे) के किरदार में नजर आ रही हैं। वीडियो पोस्ट कर उन्होंने लिखा, 'दिन को जी भरकर जियो, क्योंकि वह फिर से धमाका करने आ गई है। वेब सीरीज 'कॉल मी बे' का नया सीजन 17 दिसंबर से स्ट्रीम होगा। करण जौहर ने वेब सीरीज के दूसरे सीजन को वापस लाने को लेकर बात की। उन्होंने बताया कि नए सीजन में बे (अनन्या के किरदार का नाम) की जिंदगी के अलग-अलग पहलुओं को दिखाया जाएगा, लेकिन पहले सीजन वाला ह्यूमर, इमोशन और मस्ती वाला अंदाज बरकरार रहेगा। उन्होंने प्राइम वीडियो के साथ दोबारा जुड़ने पर खुशी जताई और कहा कि 'बे' (अनन्या के किरदार का नाम) और उसके दोस्तों को एक बार फिर हंसी, इमोशन और धमाल से भरे सफर पर ले जाने के लिए वह काफी उत्साहित हैं। नए सीजन के बारे में बात करते हुए करण जौहर ने कहा, 'सीजन-1 को मिला प्यार और रिस्पॉन्स इस बात का सबूत है कि दर्शकों ने 'बे' (अनन्या के किरदार का नाम) के उतार-चढ़ाव भरे सफर और उसकी बेबाक जिंदगी से गहरा जुड़ाव महसूस किया। सीजन 2 के साथ हम उस दुनिया को और आगे ले जाना चाहते थे, 'बे' के नए पहलुओं को दिखाना चाहते थे, लेकिन वो ह्यूमर, दिल और बिंदास अंदाज बरकरार रखना चाहते थे, जिसे सबने खूब पसंद किया था। उन्होंने आगे कहा, प्राइम वीडियो के साथ दोबारा जुड़कर हम काफी उत्साहित हैं, ताकि दर्शकों को 'बे' की जिंदगी का एक नया चैप्टर दिखा सकें, जहां वो और उसकी प्यारी बहनें हंसी, इमोशन और खूब सारे धमाल से भरे एक और सफर पर निकलेंगी। कोलिन डी'कुन्हा के डायरेक्शन में बनी इस सीरीज में अनन्या पांडे लीड रोल में हैं। उनके अलावा इसमें श्रुति हासन इस सीजन से जुड़ रही हैं। इसके साथ ही वीर दास, गुरफतेह पीरजादा, वरुण सूद, विहान समत, मुस्कान जाफरी, निहारिका लायरा दत्त, लिसा मिश्रा और मिनी माथुर भी अहम किरदारों में दिखेंगे। आठ एपिसोड वाली इस सीरीज को करण जौहर, अदार पूनावाला और अपूर्व मेहता ने धर्मैटिक एंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोड्यूस किया है। वेब सीरीज 'कॉल मी बे' 17 दिसंबर को प्राइम वीडियो पर भारत समेत दुनिया के 240 से ज्यादा देशों में स्ट्रीम होगी। **(एजेंसी)**



नेहा धूपिया को सता रहा रघु राम का डर, बोलीं- काश इस सीजन में वे नहीं होते

टेलीविजन प्रोड्यूसर और अभिनेता रघु राम 12 साल बाद लोकप्रिय एडवेंचर रियलिटी शो 'रोडीज रीबर्थ' में वापसी करने जा रहे हैं। शो की गैंग लीडर नेहा धूपिया रघुराम की इस वापसी से नाखुश नजर आ रही हैं। नेहा धूपिया ने कहा कि रघु की वापसी से वह बहुत घबराई हुई हैं। उन्होंने कहा, 'उनकी वापसी से मैं बहुत डरी हुई हूं। काश, वह इस सीजन में नहीं होते। गेम में वे पहले जो ट्विस्ट लेकर आए थे, उसने हमें काफी चौंकाया था। दरअसल, जब वे पहली बार आए थे, तो हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है।' उन्होंने आगे कहा, अगली बार जब वे फिर से लौटे, तो वे हमें और भी ज्यादा चौंकाने वाले ट्विस्ट लेकर आए थे। अब तो बस यही चाहते हैं कि हम अपना काम आराम से कर लें और रघु अचानक से न आ जाएं। बता दें कि रघु राम ने साल 2003 में शो 'रोडीज' की शुरुआत और निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी। वो शो के पहले सीजन से लेकर 11वें सीजन तक बतौर जज और मास्टरमाइंड जुड़े रहे। उनके सख्त रवैये और तीखे सवालों के चलते उन्हें टीवी का सबसे कड़क जज माना जाता था। साल 2014 में क्रिएटिव मतभेदों और प्रोड्यूसर्स के दखल के कारण रघु राम ने अपने भाई राजीव लक्ष्मण के साथ यह शो छोड़ दिया था। पूरे 12 साल के लंबे अंतराल के बाद, रघु राम एक बार फिर शो के 21वें सीजन 'रोडीज रीबर्थ' में लौट रहे हैं। इस बार वे एक खास और नई शक्ति के साथ वापसी कर रहे हैं, जिससे वे कंटेस्टेंट्स के 'मौत या पुनर्जन्म' जैसे बड़े फैसले करेंगे। 'एमटीवी रोडीज' सबसे लंबे समय तक चलने वाले एडवेंचर रियलिटी शोज में से एक है और इसका क्रेज भारतीय सीमाओं के बाहर भी कई देशों में देखने को मिलता है। **(एजेंसी)**

चीन से जरूरत से अधिक आपूर्ति के बीच टाटा स्टील ने ब्रिटेन के बाजार के लिए सरकारी मदद मांगी : नरेंद्रन

जमशेदपुर (एजेंसी)

टाटा स्टील वैश्विक तनाव, युद्ध और चीन से जरूरत से अधिक इस्पात की भारी आपूर्ति के कारण वैश्विक इस्पात कारोबार में उथल-पुथल के बीच ब्रिटेन में आयातित इस्पात के बड़े भंडार से निपटने के लिए सरकार के हस्तक्षेप की मांग कर रही है। वहीं, नीदरलैंड में अपने संयंत्र को स्वच्छ इस्पात निर्माण में बदलने के लिए सरकारी वित्तीय सहायता हासिल करने को बातचीत कर रही है।

कंपनी के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) टी. वी. नरेंद्रन ने कहा कि अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा व्यापार बाधाएं बढ़ाए जाने के बाद मूल रूप से इन बाजारों के लिए भेजा जाने वाला इस्पात ब्रिटेन की ओर मोड़ दिया गया था। उस समय ब्रिटेन में बिना



किसी पाबंदी के आयात की अनुमति थी। उन्होंने कहा, 'उन्होंने आयात की छूट पहले ही बंद कर दी है, लेकिन ब्रिटेन के बाजार में पहले से ही इस्पात का भंडार जमा है। इसलिए हम ब्रिटेन सरकार के साथ इस बारे में विशेष बातचीत कर रहे हैं कि वह बाजार को किस तरह समर्थन दे सकती है।' इसी बीच, कंपनी अपने नीदरलैंड संयंत्र को स्वच्छ इस्पात निर्माण में बदलने के लिए सरकारी सहायता हासिल करने के वास्ते वहां की सरकार के साथ बातचीत कर रही है। उन्होंने कहा, 'संयंत्र में हरित बदलाव की प्रक्रिया चल रही है, जो सरकार के समर्थन और वित्तपोषण के बिना संभव नहीं है।'

इन क्षेत्रीय व्यापार दबावों के अलावा चीन से जरूरत से अधिक आपूर्ति का भारी बोझ भी है, जिससे सालाना 40 करोड़ टन के सीमा पार इस्पात कारोबार में उथल-पुथल मची हुई है। उन्होंने कहा कि चीन हर महीने करीब एक करोड़ टन तैयार इस्पात यानी सालाना 13 करोड़ टन इस्पात का निर्यात करने के अलावा 15 करोड़ टन अन्य 'इस्पात उत्पादों' से भी वैश्विक बाजारों को भर रहा है। नरेंद्रन ने कहा, 'इसका मतलब है कि वैश्विक बाजारों पर कुल 28 करोड़ टन का असर पड़ रहा है, जिससे वैश्विक व्यापार प्रभावित हो रहा है।'

उन्होंने कहा कि आपूर्ति में इस तेजी के कारण बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को अपने इस्पात विनिर्माताओं की सुरक्षा के उपाय करने पड़े हैं। उन्होंने कहा कि यूरोप में पिछले करीब दो दशक से इस्पात की मांग लगभग स्थिर बनी हुई है। वहां नियामकों ने घरेलू इस्पात निर्माताओं की सुरक्षा के लिए आयात कोटा आधा करके तीन करोड़ टन से 1.5 करोड़ टन कर दिया है और कार्बन सीमा कर भी लागू किया है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन ने आयात पर अंकुश लगाने में देर की।

भारत-मिस्र ने द्विपक्षीय व्यापार 12 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा, निवेश और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने पर सहमति

नई दिल्ली (एजेंसी)

भारत और मिस्र ने द्विपक्षीय व्यापार को 12 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने, निवेश बढ़ाने और औद्योगिक सहयोग मजबूत करने पर सहमति जताई है। दोनों देशों ने पारस्परिक लाभ के लिए तरजीही व्यापार समझौते (पीटीए), मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) या व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) की संभावनाओं पर विचार करने के लिए एक कार्य समूह गठित करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की 15 और 16 नवंबर की मिस्र यात्रा के दौरान यह सहमति बनी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार, गोयल की यह किसी अफ्रीकी देश की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। इस दौरान उन्होंने भारत-मिस्र संयुक्त व्यापार समिति की सातवीं बैठक की सह-अध्यक्षता की और दोनों देशों के कारोबारी प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न बैठकों में हिस्सा लिया। उन्होंने मिस्र के प्रधानमंत्री डॉ. मुस्तफा मदबूली से मुलाकात की और वहां के कई मंत्रियों तथा उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से भी चर्चा की। भारत-मिस्र संयुक्त व्यापार समिति की सातवीं बैठक 15 नवंबर को गोयल और मिस्र के निवेश एवं विदेश व्यापार मंत्री डॉ. मोहम्मद फरीद सालेह की सह-अध्यक्षता में हुई।

इस समिति को मंत्रीस्तरीय स्तर पर उन्नत किया गया। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार की समीक्षा की और व्यापार के दायरे में विविधता लाने, अधिक मूल्यवर्धित निर्यात को बढ़ावा देने, बाजार तक पहुंच मजबूत करने तथा व्यापार संबंधी बाधाओं को दूर करने पर सहमति जताई।

भारत का बागवानी उत्पादन 2025-26 में 4.36% बढ़कर रिकॉर्ड 38.69 करोड़ टन रहने का अनुमान

नई दिल्ली (एजेंसी)

भारत का बागवानी उत्पादन फसल वर्ष 2025-26 (जुलाई-जून) में 4.36 प्रतिशत बढ़कर 38.69 करोड़ टन रहने का अनुमान है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को सरकार का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया। यह उत्पादन 2024-25 में दर्ज 37.07 करोड़ टन से 1.61 करोड़ टन अधिक होगा। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने कहा कि बागवानी फसलों का रकबा एक साल पहले के 3.01 करोड़ हेक्टेयर से घटकर करीब 2.97 करोड़ हेक्टेयर रहने के बावजूद उत्पादन बढ़ने का



अनुमान है। ये आंकड़े राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य सरकारी एजेंसियों से मिले आंकड़ों पर आधारित हैं। चौहान ने उत्पादन में वृद्धि का श्रेय किसानों और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार की नीतियों को दिया।

उन्होंने कहा कि किसान पारंपरिक फसलों से हटकर फल, सब्जियां, फूल, मसाले, बागान फसलों और औषधीय पौधों की खेती की ओर बढ़ रहे हैं। कृषि मंत्री ने कहा, 'व्यावसायिक और नकदी फसलों की ओर यह बढ़ता रुझान न केवल किसानों के लिए आय के नए स्रोत खोल रहा है, बल्कि कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और प्रगति के नए अवसर भी पैदा कर रहा है।' उन्होंने कहा कि उत्पादन का यह रिकॉर्ड न केवल देश की पोषण सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि बागवानी करने वाले किसानों की आय भी सीधे तौर पर बढ़ाएगा। फल उत्पादन 2025-26 में 4.60 प्रतिशत बढ़कर 12.30 करोड़ टन रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष 11.76 करोड़ टन था।

प्री-बजट बैठक : सीतारमण ने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से की बातचीत

नई दिल्ली (एजेंसी)



वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के पक्षकारों के साथ प्री-बजट बैठक की। इसमें उन्होंने विशेषज्ञों और उद्योग के जानकारों से विकास के अवसरों और नीतियों के लेकर बातचीत की। वित्त मंत्रालय के अनुसार, इस बैठक में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों को बुलाया गया था।

इसका उद्देश्य क्षेत्र से जुड़ी चिंताओं, विकास के अवसरों और उन नीतिगत उपायों पर चर्चा करना था, जिन पर आगामी बजट में विचार किया जा सकता है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में बताया कि इस बैठक में सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। इनमें आर्थिक मामलों के विभाग, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), खान मंत्रालय और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव, और मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन मौजूद थे। यह हालिया बैठक वित्त मंत्रालय की उस वार्षिक 'प्री-बजट' बैठकों का हिस्सा है, जिसका मकसद बजट प्रस्तावों को अंतिम रूप देने से पहले अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों से सुझाव जुटाना है।

मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को लेकर हुई यह चर्चा, वित्त मंत्री सीतारमण की अध्यक्षता में इस सप्ताह की शुरुआत में हुए कई बैठकों का हिस्सा है। इससे पहले सोमवार को वित्त मंत्री ने कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्रों के विशेषज्ञों और पक्षकारों के साथ दूसरी 'प्री-बजट' बैठक की थी। इन चर्चाओं में ग्रामीण विकास को मजबूत करने, किसानों की आय बढ़ाने और व्यापक अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान को बेहतर बनाने के उपायों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

इस बैठक में आर्थिक मामलों के विभाग, मत्स्य पालन विभाग और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। उसी दिन, वित्त मंत्री ने प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ परामर्श के पहले दौर की अध्यक्षता की। इसमें आगामी वित्तीय वर्ष के लिए व्यापक आर्थिक रुझानों, विकास की संभावनाओं और नीतिगत प्राथमिकताओं पर उनके विचार मांगे गए। इसके अलावा, परामर्श प्रक्रिया के हिस्से के रूप में सरकार उद्योग निकायों के साथ भी बातचीत कर रही है। हाल ही में पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ हुई बातचीत में, उद्योग प्रतिनिधियों ने प्रमुख औद्योगिक कच्चे माल और ऊर्जा इनपुट पर सीमा शुल्क को तर्कसंगत बनाने की मांग की, जिससे एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बेहतर बनाया जा सके।